



छत्तीसगढ़ पुलिस धोएं क्या, निचोड़ें क्या वाली स्थिति

गृह और वित्त मंत्रालय में उलझी पुलिस भत्ते की फाइल

पुलिसकर्मियों के भत्तों में वर्षों से वृद्धि नहीं

सुविधा देने में अन्य राज्यों से पिछड़ा छग.

मुख्य संवादाता/विकास यादव

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश पुलिस में आरक्षकों से लेकर थाना प्रभारियों तक को शासन से प्राप्त भत्ता ऊंट के मुंह में ज़ीरा साबित हो रहा है। वर्दी अलाउंस, धुलाई भत्ता, पौष्टिक आहार आदि देय भत्तों में अन्य राज्यों की तुलना में जमीन-आसमान का अंतर है। महंगाई और दैनिक लागत में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। महंगाई दर (2011-2024): लगभग 70% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्दी, जूते और अन्य सामग्री की लागत: 80-90% तक बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर अन्य कई राज्यों ने महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिक रिवीजन का प्रावधान भी लागू किया है। पुलिस मैनुअल में यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक 5 वर्ष में सेवा शर्तों और भत्तों की समीक्षा अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 के बाद से अब तक किसी भी प्रकार की भत्तों की समीक्षा नहीं की गई है। यह स्थिति मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन मानी जा सकती है। परिणामतः पुलिसकर्मियों को भत्ते से बहुत अधिक निजी खर्च उठाना पड़ रहा है, जो सेवा संतुष्टि और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।



छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों को वर्तमान में मिलने वाला प्रमुख भत्ता

वर्दी धोने का भत्ता	: ₹100 प्रति माह
जूते भत्ता	: ₹300 प्रति वर्ष
राशन भत्ता	: ₹1,000 प्रति माह
पौष्टिक आहार भत्ता	: ₹100 प्रति माह

यह दरें लगभग वर्ष 2011 से अपरिवर्तित हैं, आरक्षक से थाना प्रभारियों के भत्ते में अंतर है।

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के जवानों और अधिकारियों को वर्दी धोने, जूते खरीदने और राशन हेतु भत्ते पुलिस मैनुअल के अनुसार दिए जाते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से इन भत्तों में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि महंगाई और जीवन यापन की लागत में भारी इजाफा हुआ है। पौष्टिक अहार से लेकर, धुलाई भत्ता 50 से 60 रूपए है। महिने

भर का एक बार का पुलिस विभाग का ये भत्ता ऊंट के मुंह में ज़ीरा सामान है। नाममात्र पौष्टिक आहार भत्ता में 100 रूपए का सेब खरीदे तो उसको खाने के बदले देखकर पेट भरके पौष्टिकता ग्रहण करना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों के भत्ते देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं और वर्षों से संशोधित नहीं हुए

हैं। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए, पुलिस कर्मचारियों की मांग है कि राज्य सरकार शीघ्र भत्तों में वृद्धि कर उनकी सेवा शर्तों में सुधार करे। छत्तीसगढ़ में एक भेदभाव और किया जा रहा जिसमें फ़िल्ड वाले को नहीं सिर्फ थान पोस्टिंग को ही रिस्क अलाउंस 1000 देय है।

कर्मचारी कोड:	आईडी:		
बिल सफल:	शुद्ध राशि:		
पदनाम: HEAD CONST	स्थान:		
-----आहरण-----			
बैसिक:39600	डी.ए.:19800	GIS.:300	GPF/DPF-5000
P.AaharAll.:100			
Uni.Allow.:60			
Trains.all.:100			
C.C.A.:75			
Spec.pay.:30			
कुल प्राप्य राशि: 59765	कुल कटौती: 5300	कुल वेतन: 54465	

मांग उठी पर शासन को जूं नहीं रेंगी

2014

पुलिसकर्मियों ने पहली बार भत्तों में संशोधन की मांग उठाई। मुख्यतः वर्दी धोने और राशन भत्ते को बढ़ाने की मांग की गई थी। सरकार ने विचार का आश्वासन दिया लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

2017

पुनः मांग उठी। महंगाई दर बढ़ने के कारण राशन भत्ते को ₹2,000 प्रति माह करने की मांग की गई थी। पुलिस एसोसिएशनों ने लिखित ज्ञापन भी सौंपा था। उस समय सरकार ने "बजट सीमाओं" का हवाला देते हुए मांग को टाल दिया।

2020

(COVID-19 के दौरान)

लॉकडाउन के समय पुलिस ने चौबीसों घंटे ड्यूटी दी। पुलिस संगठनों ने विशेष भत्ता और मौजूदा भत्तों में वृद्धि की मांग दोबारा की। महामारी के चलते तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन मांग दर्ज की गई थी।

2022

महंगाई और डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद पुलिस कर्मचारी संगठनों ने फिर से मांग उठाई। वर्दी के बढ़े हुए खर्चों को आधार बनाकर वर्दी धोने भत्ते को कम से कम ₹300 प्रति माह करने की मांग हुई। तब भी सिर्फ विभागीय स्तर पर समीक्षा का भरोसा दिया गया, पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

2024

(वर्तमान स्थिति)

एक बार फिर पुलिस कर्मचारी संगठनों ने राशन भत्ता ₹2,500 प्रति माह और अन्य भत्तों में संशोधन की मांग की है। ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और बजट सत्र में प्रस्ताव लाने की संभावना बताई जा रही है।

शासन का रुख अब तक स्पष्ट नहीं



जानकारी में मुताबिक आगामी राज्य बजट सत्र में पुलिस भत्तों में संशोधन को लेकर एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालाँकि, इस संबंध में अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि सख्त और हाड़ तोड़ ड्यूटी करने वाले कानून के रक्षक ही जब विभागीय और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से आर्थिक दरिद्री झेलेंगे तो उनके लिए अन्य विकल्प खोजना फिर मजबूरी बन जाती है।

समिति का कार्य उद्देश्य

- वर्दी धोने का भत्ता, जूते का भत्ता, राशन भत्ता आदि की दरों का पुनरीक्षण करना।
- अन्य राज्यों से तुलना करना और रिपोर्ट तैयार करना।
- वित्तीय भार का आकलन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना।
- भविष्य के लिए भत्तों की नियमित समीक्षा प्रणाली का सुझाव देना।

आला अफसरों ने सौंप चुकी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ पुलिस भत्ते पुनरीक्षण समिति (2022-2023) की समिति ने 2023 के प्रारंभ में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग से सिफारिशें लंबित हैं। अंतिम निर्णय कैबिनेट स्तर पर होना बाकी है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा बनाई गई इस समिति में निम्न अधिकारी शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG, प्रशासन) अध्यक्ष, उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG, कल्याण) सदस्य सचिव, पुलिस अधीक्षक (SP, मुख्यालय) सदस्य, सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP, स्थापना शाखा) सदस्य, उप संचालक, लेखा विभाग (PHQ) वित्तीय सलाहकार सदस्य, अधीक्षक, पुलिस कल्याण विभाग विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

पुलिसकर्मियों की मांगें

छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारी संगठन के एक प्रतिनिधि ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "हमसे 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन मिलने वाला वर्दी भत्ता आज के समय में प्रतीकात्मक ही रह गया है। सरकार को चाहिए कि पुलिस मैनुअल के अनुसार हर 5 साल में समीक्षा कर भत्तों में समुचित बढ़ोतरी करे। वर्दी और जूते की लागत दोगुनी हो गई है, लेकिन भत्ते वहीं के वहीं हैं।"

आंतरिक समिति का कार्य खत्म

आंतरिक समिति का उद्देश्य था राज्य पुलिस के भत्तों से लेकर अन्य मामलों की रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट आला अफसरों ने तैयार भी किया लेकिन गृह और वित्त मंत्रालय की उदासीनता से यह पेंडिंग है। इसमें आरक्षक से थाना प्रभारी स्तर के लिए वर्दी, जूते, राशन भत्तों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना। अन्य राज्यों के भत्तों की तुलना कर रिपोर्ट तैयार करना। भत्तों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार को रिपोर्ट भेजना शामिल था।

समिति की प्राथमिक सिफारिशें

वर्दी धोने का भत्ता ₹300 प्रति माह करने की अनुशंसा। जूते का भत्ता ₹1,000 प्रति वर्ष करने का सुझाव। राशन भत्ता ₹2,000 से ₹2,500 प्रति माह के बीच बढ़ाने का प्रस्ताव। हर 5 वर्ष में स्वतः समीक्षा का सिस्टम लागू करने की सिफारिश।

ठंडे बास्ते में समिति की रिपोर्ट

समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 2023 की शुरुआत में पुलिस मुख्यालय को सौंपी थी। रिपोर्ट को राज्य गृह विभाग को भेजा गया, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ।

राज्य सरकार से समिति हुई रूबरू

वर्ष 2023 में गृह विभाग और वित्त विभाग के साथ 2 दौर की बैठकें हुईं। फंडिंग और वित्तीय भार का आकलन करने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र 2025 में प्रस्ताव रखने की तैयारी है।

वित्तीय बोझ से पुलिस की अनदेखी

वित्तीय बोझ बढ़ने का हवाला देते हुए प्रक्रिया धीमी चल रही है। राज्य में अन्य सामाजिक योजनाओं पर भी भारी व्यय हो रहा है, जिससे प्राथमिकता में बदलाव हुआ है। चुनावी साल (2023) के चलते निर्णय टल गया था।

“

समय-समय पर पुलिस मैनुअल को अपडेट करने के लिए विभागीय स्तर पर शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है। इस मामले में वक्तव्य देने का अधिकार मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को है। डॉ. लाल उमेश सिंह, एसएसपी रायपुर

“

पुलिसकर्मी हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों। ऐसे में उन्हें मिलने वाले भत्तों का समयानुकूल संशोधन होना बेहद जरूरी है, ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर सकें। राजेश झा, डीएसपी बेमेतरा

इन राज्यों में हुआ पुलिस मैनुअल में संशोधन

महाराष्ट्र (2022)

भत्तों के अलावा सर्विस रूल्स में भी सुधार किया गया, जिसमें नाइट ड्यूटी भत्ता और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जोड़े गए।

वर्दी धोने का भत्ता	: ₹200 प्रति माह
जूते का भत्ता	: ₹500 प्रति वर्ष
राशन भत्ता	: ₹1,500 प्रति माह
संशोधन वर्ष	: 2022

मध्य प्रदेश (2023)

वर्दी, जूते, राशन भत्ते की राशि बढ़ाई गई। पुलिस आवास सुविधा में भी सुधार के निर्देश जारी किए गए।

वर्दी धोने का भत्ता	: ₹200 प्रति माह
जूते का भत्ता	: ₹500 प्रति वर्ष
राशन भत्ता	: ₹1,800 प्रति माह
संशोधन वर्ष	: 2023

तमिलनाडु (2021)

कोरोना के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए अतिरिक्त जोखिम भत्ता भी दिया गया।

वर्दी धोने का भत्ता	: ₹250 प्रति माह
जूते का भत्ता	: ₹600 प्रति वर्ष
राशन भत्ता	: ₹2,000 प्रति माह
संशोधन वर्ष	: 2021

गुजरात (2022)

कुछ भत्तों को महंगाई के अनुसार ऑटोमैटिकली रिवाइज करने की व्यवस्था लागू की गई।

उत्तर प्रदेश

वर्दी धोने का भत्ता	: ₹150 प्रति माह
जूते का भत्ता	: ₹400 प्रति वर्ष
राशन भत्ता	: ₹1,200 प्रति माह
संशोधन वर्ष	: 2019

राजस्थान

वर्दी धोने का भत्ता	: ₹180 प्रति माह
जूते का भत्ता	: ₹450 प्रति वर्ष
राशन भत्ता	: ₹1,600 प्रति माह
संशोधन वर्ष	: 2022



नौकरशाहों ने शासन को सौंपा संपत्ति का ब्यौरा

छत्तीसगढ़ के IAS और IPS अफसरों की करोड़ों की संपत्ति हुई सार्वजनिक



रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस और आईपीएस नौकरशाहों ने इस साल अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा राज्य शासन को सौंपा है। संपत्ति के ब्यौरा के अनुसार प्रदेश के कई IAS और IPS अधिकारी करोड़पति हैं। प्रदेश कुल 10 कलेक्टरों और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपनी करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। वहीं, 19 अफसर ऐसे भी हैं, जिनके पास खुद के नाम पर कोई निजी मकान नहीं है।

IAS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण

- रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे ने सबसे अधिक ₹3.5 करोड़ की संपत्ति घोषित की है।
- बिलासपुर कलेक्टर जनमेजय महोबे के पास ₹2.8 करोड़ की संपत्ति है।
- दुर्ग कलेक्टर गौरव सिंह ने ₹2.5 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया है।
- राजनांदगांव कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने ₹2.2 करोड़ की संपत्ति घोषित की।
- कोरबा कलेक्टर सौरभ कुमार के पास ₹2 करोड़ की संपत्ति है।
- रायगढ़ कलेक्टर प्रियंका शुक्ला की संपत्ति ₹1.8 करोड़ है।
- बस्तर कलेक्टर अभिषेक सिंह ने ₹1.5 करोड़ की संपत्ति घोषित की है।
- कांकेर कलेक्टर निखिल चंद्राकर के पास ₹1.3 करोड़ की संपत्ति है।
- जांजगीर-चांपा कलेक्टर शिव अनंत तायल की संपत्ति ₹1.2 करोड़ है।
- महासमुंद कलेक्टर राहुल देव ने ₹1 करोड़ की संपत्ति घोषित की है।

कई अधिकारियों ने कृषि भूमि, गहने और अन्य प्रकार के निवेश को अपनी संपत्ति में शामिल किया है।

संपत्ति घोषणाएं हर साल अनिवार्य

प्रशासनिक नियमों के तहत राज्य के IAS और IPS अधिकारियों के लिए हर वर्ष 31 मार्च तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण सरकार को देना अनिवार्य है। इस वर्ष सभी अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा समय पर प्रस्तुत किया।

IPS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण

- छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने ₹5 करोड़ की संपत्ति घोषित की है, जो राज्य के पुलिस अधिकारियों में सबसे अधिक है।
- रायपुर रेंज के आईजी अजय यादव के पास ₹3.2 करोड़ की संपत्ति है।
- रायपुर एसपी संदीप पिल्ले ने ₹2.6 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है।
- दुर्ग एसपी ललित शुक्ला के पास ₹2.1 करोड़ की संपत्ति है।
- बिलासपुर एसपी श्रद्धा चौहान ने ₹1.9 करोड़ की संपत्ति घोषित की है।

IPS अधिकारियों ने भी कृषि भूमि, गहने और विभिन्न प्रकार के निवेशों में संपत्ति अर्जित करने की जानकारी दी है। कुछ अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भी है।

संपत्ति में तेजी से वृद्धि

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई IAS और IPS अधिकारियों की संपत्ति पिछले सात वर्षों में दोगुनी हो गई है। कई युवा अधिकारी जिन्होंने हाल के वर्षों में सेवा शुरू की थी, उन्होंने भी अब तक करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है। संपत्ति के इस बढ़ते ग्राफ ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, हालांकि सभी अधिकारियों ने इसे वैध स्रोतों से अर्जित बताया है।

11 जिलों के बदले कलेक्टर 41 IAS का ट्रांसफर

सचिव IAS सर्वेश्वर भुरे को जिला की कमान ठेका विवाद पर हटाए गए कलेक्टर आकाश छिकारा



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक शल्यक्रिया बड़े पैमाने पर किया है। प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ IAS अधिकारियों के प्रभार और जिम्मेदारियों को बदलने का नया आदेश जारी किया है। शासनादेश पर छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं तो वहीं कुल 41 IAS अफसरों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। इसमें सचिव प्रभार के अधिकारी को बतौर कलेक्टर बनाया गया है तो वहीं कुछ कलेक्टरों को

लापरवाही, उदासीनता के चलते डंप कर दिया गया है। लिस्ट के मुताबिक कुणाल दुदावत को दंतेवाड़ा का कलेक्टर बनाया गया है। मयंक चतुर्वेदी रायगढ़ जिले के नए कलेक्टर होंगे। संजय कन्नौजे सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर होंगे, नूपुर राशि पन्ना को कोंडागांव जिले का कलेक्टर बनाया गया है। कुंदन कुमार को मुंगेली जिले का कलेक्टर बनाया गया है। देखिये किस IAS को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है...

इन IAS के कार्यों में बदलाव

- चर्चा में रहने वाले अधिकारी जनक प्रसाद पाठक अब वन विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं।
- डॉ प्रियंका शुक्ला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक बनी हैं।
- किरण कौशल को मार्कफेड और नान में प्रबंध संचालक बनाया गया है।
- रायगढ़ के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल को खाद्य नागरिक आपूर्ति का संचालक बनाया गया है।
- विकास कार्य की धीमी गति की वजह से मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव को भी हटाया गया है।
- जांजगीर से हटाए गए कलेक्टर आकाश छिकारा को आवास पर्यावरण विभाग का उप सचिव बनाया गया है।
- बिलासपुर कलेक्टर अनीश कुमार शरण को कलेक्टर पद से हटाकर गृह निर्माण मंडल का आयुक्त बनाया गया है।
- रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल को हटाकर खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग का संचालक पदस्थ।
- सारंगढ़ जिले के कलेक्टर धर्मेस साहू को हटाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है।
- गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का नियंत्रक बनाया गया है।
- जन्मेजय महोबे को जांजगीर जिले का कलेक्टर बनाया गया है।
- सर्वेश्वर भुरे को राजनांदगांव जिले का कलेक्टर बनाया गया है।
- दिव्या उमेश मिश्रा को बालोद जिले का कलेक्टर बनाया गया है।
- संजय अग्रवाल को बिलासपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है।
- इंद्रजीत चंद्रवाल को खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का कलेक्टर बनाया गया है।

पवन देव पुलिस हाऊसिंग अजातशत्रु गुप्तवार्ता सम्हालेंगे



शहर सत्ता/रायपुर। राज्य शासन ने दिन पहले आईएएस के थोक में तबादले के बाद अब थोक में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। रविवार को एक साथ किए गए 20 आईपीएस के तबादले में पवन देव से लेकर अंकित गर्ग, ध्रुव गुप्ता, दीपक कुमार झा से लेकर विजय पांडे तक शामिल हैं।

इन आईपीएस अधिकारियों का बदला प्रभार ...

- पवन देव (भापुसे-19952004) को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन, रायपुर के अतिरिक्त अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है।
- अंकित कुमार गर्ग (भापुसे-2004), पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, को पुलिस महानिरीक्षक, एसआईबी, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर नियुक्त किया गया।
- ध्रुव गुप्ता (भापुसे-2005), पुलिस महानिरीक्षक, एसआईबी, को पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, नवा रायपुर बनाया गया। उन्हें सीसीटीएनएस/एससीआरबी और तकनीकी सेवाओं का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वे 30 अप्रैल 2025 के बाद सीआईडी का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- दीपक कुमार झा (भापुसे-2007) को पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, और श्री अभिषेक शांडिल्य (भापुसे-2007) को पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव रेंज नियुक्त किया गया।
- बालाजी राव सोमावार (भापुसे-2007) को पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर का दायित्व सौंपा गया।
- अजातशत्रु बहादुर सिंह (भापुसे-2011) को पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, विशेष शाखा, और विवेक शुक्ला (भापुसे-2012) को एआईजी, सीआईडी, पुलिस मुख्यालय नियुक्त किया गया।
- राजेश कुमार अग्रवाल (भापुसे-2012) को पुलिस अधीक्षक, सरगुजा, विजय अग्रवाल (भापुसे-2012) को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, और श्रीमती भावना गुप्ता (भापुसे-2014) को पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा बनाया गया।
- सूरज सिंह (भापुसे-2015) को पुलिस अधीक्षक, धमतरी, और त्रिलोक बंसल (भापुसे-2016) को पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा नियुक्त किया गया।
- अंजनेय वार्षीय (भापुसे-2018) को पुलिस अधीक्षक, सारंगढ़-बिलाईगढ़, और योगेश कुमार पटेल (भापुसे-2018) को पुलिस अधीक्षक, बालोद बनाया गया।
- एस.आर. भगत (भापुसे) को पुलिस अधीक्षक, गौरला पेंड्रा मरवाही, और विजय पाण्डे (भापुसे) को पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के पद पर तैनात किया गया।

द्वार-द्वार सुशासन की खुशियाँ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में शुरू हुआ सुशासन तिहार द्वार-द्वार तक सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। इस तिहार का उद्देश्य जनसरोकार से जुड़े मामलों, शिकायतों का त्वरित निराकरण करना और हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को बढ़ावा देने वाले इस अभियान के तहत शासन की योजनाओं को आम नागरिकों तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है।



शम्भूनाथ के राशन कार्ड में जुड़े दो सदस्यों के नाम



बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत धुरगांव निवासी शम्भूनाथ कश्यप के परिवार में पहले केवल दो सदस्य माता समली कश्यप और वह स्वयं ही थे लेकिन तीन वर्ष पहले विवाह होने के बाद पत्नी महादई कश्यप और दो साल का बेटा प्रभात भी अब परिवार में सदस्य हैं। इन दोनों का नाम उन्हें प्रदत्त प्राथमिकता राशनकार्ड में शामिल नहीं था। इसे देखते हुए शम्भूनाथ ने राशनकार्ड में अपनी पत्नी और बेटे का नाम जुड़वाने के लिए सुशासन तिहार के अंतर्गत 11 अप्रैल को आवेदन ग्राम पंचायत में जमा किया था, उक्त आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर ही

नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत दीपा को मिली सहायता



महासमुंद शहर के वार्ड नं. 25 की दीपा साहू ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत आवेदन किया था। पात्रता जांच के बाद उन्हें 20,000 रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है, जो एक मई को सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि दीपा की शिक्षा में काम आएगी। उनका सपना है कि वह शिक्षिका बनकर समाज को नई दिशा दें। सुशासन तिहार का उद्देश्य जनसरोकार से जुड़े मामलों, शिकायतों का त्वरित निराकरण करना और हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना है।

सुदर्शन को मिली ट्रायसाइकिल



समाज कल्याण विभाग रायगढ़ द्वारा पुसौर विकासखंड के ग्राम ओड़ेकेरा निवासी सुदर्शन खड़िया को ट्रायसाइकिल और बैसाखी उपलब्ध कराई गई। सुदर्शन 80 प्रतिशत दिव्यांग हैं और लंबे समय से आवागमन में कठिनाई का सामना कर रहे थे। ट्रायसाइकिल मिलने पर उन्होंने कहा कि अब उन्हें कहीं भी आने-जाने में सुविधा होगी और वे दूसरों पर कम निर्भर रहेंगे। उन्होंने सुशासन तिहार की सराहना करते हुए इसे आमजन के लिए संवाद से समाधान की दिशा में एक सशक्त पहल बताया।

पतेरपाली की युगेश्वरी को मिला खुद का आशियाना



महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पतेरपाली की निवासी श्रीमती युगेश्वरी धुव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान के लिए सुशासन तिहार के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया। "मोर द्वार साय सरकार" अभियान के तहत जिले की टीम तुरंत उनके घर पहुंची। त्वरित सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वे योजना की पात्र हैं। उनका नाम आवास प्लस सर्वे 2.0 में दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उनके मकान का निर्माण शुरू हो जाएगा। वर्षों से पक्के घर का सपना संजोर बैठी श्रीमती धुव की आंखों में अब उम्मीद की चमक है।

अनीता का तत्काल बना श्रमिक कार्ड



रायगढ़ जिले के ग्राम ननसिया की श्रीमती अनीता बाई ने श्रमिक पंजीयन और श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था। इसका तत्काल निराकरण करते हुए उनका पंजीयन कर श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं और पात्रता संबंधी जानकारी भी दी गई। श्रम विभाग द्वारा महतारी जतन, छात्रवृत्ति, नोनी सशक्तिकरण, मृत्यु पर परिवार को सहायता, सियान योजना, पेंशन योजना, साइकिल, सिलाई मशीन तथा अन्य उपकरण प्रदान करने से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

24 घंटे में बना मनोहर का आयुष्मान कार्ड



पिथौरा विकासखंड के ग्राम जंधोरा निवासी मनोहर सिंह पटेल को तकनीकी कारणों से पहले आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया था। उन्होंने सुशासन शिविर में शिकायत दर्ज कराई, जिसे केवल 24 घंटे में सुलझाया गया। 16 अप्रैल को उन्हें उनका कार्ड मिल गया जिससे अब वे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे। सुशासन तिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता की समस्याओं को सुनना और समाधान देना। इससे न सिर्फ सरकारी योजनाओं पर भरोसा बढ़ा है बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद और विश्वास भी मजबूत हुआ है।

दिव्यांग बैगा आदिवासी को मिली ट्राइसिकल



सुशासन तिहार के दौरान श्री मंगल सिंह बैगा ने ट्राइसिकल और पेंशन के लिए आवेदन 10 अप्रैल को दिया था। उन्हें 11 अप्रैल को ही समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्राइसिकल प्रदान करने की सूचना दी गई। लेकिन उन्होंने 15 अप्रैल को ट्राइसाइकिल लिया। विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उनकी पेंशन के लिए पात्रता नहीं बन पा रही थी। समाज कल्याण विभाग द्वारा उनका विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा दिया गया है। वे अब पेंशन की पात्रता सूची में आ गए हैं। जल्द ही उन्हें पेंशन भी मिलने लगेगी। मंगल सिंह बैगा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया।

भारती देवांगन को तत्काल मिला श्रमिक कार्ड



राजनांदगांव के शीतला माता वार्ड निवासी श्रीमती भारती देवांगन की समस्या का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया और उन्हें तत्काल श्रमिक कार्ड बनाकर दिया गया। सुशासन तिहार अंतर्गत श्रीमती भारती देवांगन ने श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत श्रमपदाधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में आवेदन किया गया था। इस पर श्रम विभाग में तत्काल पंजीयन किया गया एवं श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया। श्रीमती भारती देवांगन ने कहा कि श्रमिक कार्ड मिलने से राहत मिली है।

संपादकीय

○ सुकांत राजपूत



गरीबों के पेट पर लात

वैसे तो रंग बदलने में सिर्फ गिरगिट ही माहिर है। वर्तमान में रायपुर नगर निगम की शहरी सत्ता के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। रईसों के सामने नतमस्तक होते और राजधानी में दो जून की रोजी-रोटी के लिए जद्दोजहद करते गरीबों को लतियाते हुए निगम अमले को देखा जा सकता है। स्टार बक्स, बनाना लीफ, टिनी टॉयज जैसे आउटलेट्स की बदइंतजामी को नजर अंदाज करने वाला रायपुर नगर निगम, निगम कमिश्नर, जोन कमिश्नर समेत पूरी शहरी सत्ता गरीबों के ठेले-खोमचों को बुलडोजर तले रौंदने में मशगूल है। सुबह से देर रात तक टपरी में परिवार की रोटी के लिए जूझती राधा बाई और पुनाराम देवदास जैसे कई मजबूर हैं। करोना काल से ही जो पान और चाय टपरी बंद थी उसे निगम कमिश्नर के आदेश पर जोन-4 कमिश्नर अरुण ध्रुव ने जेसीबी बुलाकर रौंद दिया। रोड से दूर, नाली के किनारे लकड़ियों की छोटी सी घुन लगी टपरी की जितनी कीमत नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा उसे तोड़ने के लिए निगम के नाकाबिल अफसरों ने महकमे का पैसा खर्च कर दिया। शहरी सत्ता के इन बहादुरों की इस कार्रवाई की वजह थी सिर्फ स्टार बक्स, बनाना लीफ जैसे फूड जोन में आने वाले रईसों की करें की पार्किंग के लिए बंदोबस्त करना। मजे की बात ये नामचीन आउटलेट्स जिस बिल्डिंग में चल रहे हैं उसमें कोई पार्किंग सिस्टम ही नहीं है। सवाल उठता है इतने कबीलों की नाकाबिलियत से कैसे एक वीआईपी मूवमेंट वाले मुख्य मार्ग और सिविल लाइन जैसे इलाके में बिना पार्किंग के नक्शा पास कर दिया गया?

ट्रैफिक हो या फिर ड्रेनेज सिस्टम अगर राजधानी को कोई भी कब्जाधारी फिर चाहे वो रईस हो या मुफलिस खराब कर रहा है तो कार्रवाई जायज है। लेकिन निगम की नजर में अगर सिर्फ गरीब ही कब्जाधारी है, क्योंकि वह छोटी सी गुमटी निगम की जगह में लगा रहा है तो जिम्मेदारों को उन रईसों के बंगलों के सामने सड़क का आधा हिस्सा घेरकर लगाए गार्डन या हादसों को दावत देती सड़क पर पार्क महंगी गाड़ियों पर भी नजर डालना चाहिए। सीएम, राज्यपाल, मंत्रियों का काफिला सिविल लाइन बंगलों से पुलिस लाइन हेलीपेड इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है जहां बिना पार्किंग सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम के महंगे फूड आउटलेट्स सुबह से देर रात तक चल रहे हैं। लेकिन इनपर एक्शन लेने के बदले इनकी पार्किंग व्यवस्था के लिए गरीबों के पेट में लात मारना निगम बंद नहीं किया तो फिर चुनाव में कोई पार्टी बिछिया, साड़ी, पैसा, दारू भी देगी तो वह सत्ता तो दूर शहरी सत्ता से भी हाथ धो बैठेगी। यही गुजारिश है सभी को व्यवस्था दें एक से छीनकर दूसरे के मुंह का कौर नहीं डालें जिम्मेदार।



बाल श्रम कानून लागू करई ल लेके कतकों बेर भेदभाव देखे ले आथे जी भैरा.

अट्टारा बछर ले कमती उमर के लड़का मन जब रोजी मजूरी या कहिन पइसा कमाए खातिर बुता करथें त ए हलागुहोथे जी कौंदा.

हव गा.. महुँ ल अतका के जानबा हे, फेर मोला लागथे के एमा जबर पक्षपात होथे.. अब कालेच के बात देख ले हमर रायपुर के रविभवन म 6 झन लड़का मनला मोबाइल रिपेयरिंग दुकान म बुता करत हें कहिके वो दुकान के संचालक मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे गे हवय.

हाँ त बने तो करे हे.

फेर मोर कहना ए हे संगी- पइसा कमाए के उद्देश्य ले ही कतकों नाबालिग लड़का मन क्रिकेट या अन्य प्रोफेशनल खेल म भाग लेथें, त फेर उँकर मन ऊपर ए कानून हलागुकाबर नइ होवय?

वाह भई.. कहना तो तोर वाजिब हे.

अभी इहाँ आईपीएल चलत हे न.. इहू म एक दू नाबालिग लड़का मन कोनो कोनो टीम म हावयँ, जे मन व्यावसायिक रूप ले माने पइसा कमाए के नाँव म ही क्रिकेट खेलत हें.. अउ अतकेच भर नहीं.. ए मन अपन आने सिनियर खेलइया मन बर मैदान भीतर पानी अउ डूँक धर के लेगथें या कहिन डोहारत रहिथें.. अब तहीं बता ए ह बाल श्रम कानून के अंतर्गत आही के नहीं?

छत्तीसगढ़ के लोक-देवता देवी करिया धुरवा

स्वराज करुण

दुनिया के अधिकांश ऐसे देशों में जहाँ गाँवों की बहुलता है और खेती बहुतायत से होती है, जहाँ नदियों, पहाड़ों और हरे-भरे वनों का प्राकृतिक सौन्दर्य है, ग्राम देवताओं और ग्राम देवियों की पूजा-अर्चना वहाँ की एक प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता मानी जाती है। सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, अग्नि, वायु, जल और वर्षा की चमत्कारिक प्राकृतिक शक्तियों ने इन्हें भी प्राचीन काल से ही लोक-मानस में देवताओं और देवियों के रूप में प्रतिष्ठित किया। चाहे नील नदी और सहारा रेगिस्तान का देश मिस्र हो या अफ्रीकी महाद्वीप के छोटे-बड़े देश, चाहे एशिया महाद्वीप का चीन हो या भारत, सभी देशों में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनके अपने-अपने देवी-देवता होते हैं। भारतीय संस्कृति में तो प्राचीन काल से ही नदियों, पहाड़ों और वनों को भी देवी-देवता के रूप में पूजा जाता है और मानव समाज के प्रति उनके अमूल्य और अतुलनीय योगदान के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया जाता है। राजतंत्र के जमाने में प्रत्येक राजवंश के स्वयं के कुल देवता और कुल-देवियाँ हुआ करती थी।



जन्म भूमि और कर्म भूमि के रूप में विख्यात है। अंचल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शिवशंकर पटनायक की सशक्त लेखनी से करिया धुरवा की जीवन गाथा पहली बार उपन्यास के रूप में सामने आयी है। पिथौरा निवासी श्री पटनायक रामायण और महाभारत के पात्रों पर आधारित कई पौराणिक उपन्यासों के सिद्धहस्त लेखक हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, यह छत्तीसगढ़ के किसी लोक-देवता पर केन्द्रित पहला उपन्यास है। करिया धुरवा इस उपन्यास के नायक हैं, वहीं इसमें मानसाय और नोहर दस्यु जैसे अत्याचारी खलनायक भी हैं। किसी भी अत्याचारी खलनायक की तरह उनका भी अंत बहुत बुरा होता है। उपन्यास में जन-कल्याणकारी लोकप्रिय शासकों के रूप में कोसल महाराजा और सिंहगढ़ नरेश प्रियभान के चरित्र को भी रोचक ढंग से उभारा गया है। करिया धुरवा और उनकी पत्नी देवी कुंअर के नाम पर उपन्यास का शीर्षक 'देवी करिया धुरवा' रखा गया है। नायिका देवी कुंअर को इसमें एक जागरूक, सशक्त और साहसी नारी के रूप में चित्रित किया गया है।

अर्जुनी में करिया धुरवा का मंदिर

उनका बहुत प्राचीन और इकलौता मंदिर राजधानी रायपुर से तकररीबन 100 किलोमीटर और तहसील मुख्यालय पिथौरा से लगभग छह किलोमीटर पर ग्राम अर्जुनी में स्थित है। मुम्बई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 के किनारे ग्राम मुढीपार से होकर अर्जुनी की दूरी सिर्फ दो किलोमीटर है। हर साल अगहन पूर्णिमा के मौके पर जन-सहयोग से तीन दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आम तौर पर यह करिया धुरवा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अनेक आंचलिक देवी-देवताओं की

पूजा, परंपरा और संस्कार

अब तो राजतंत्र नहीं है, लेकिन कुल देवों और कुल देवियों की पूजा की परंपरा उनके यहाँ पीढ़ी दर-पीढ़ी आज भी चली आ रही है। यहाँ तक कि हम जैसे सामान्य मनुष्यों के भी अपने कुल देवता और कुल देवियाँ होती हैं। हमारे यहाँ जनजातीय समाजों के भी अपने-अपने आराध्य देव और अपनी-अपनी आराध्य देवियाँ हैं। कई मनुष्य भी अपनी विलक्षण प्रतिभा, अपने शौर्य, अदम्य साहस और लोक हितैषी कार्यों की वजह से समाज में सम्मानित होकर लोक मानस में देवी-देवता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। उन्हें अलौकिक और अतुलनीय शक्तियों का केन्द्र मान लिया जाता है। आगे चलकर वे व्यापक जन-आस्था का केन्द्र बन जाते हैं। उन्हें लोक-देवता अथवा लोक-देवी के रूप में लोक-मान्यता मिल जाती है।

हर गाँव और ग्राम समूहों के अपने देवी-देवता

कृषि प्रधान भारत के ग्रामीण परिवेश वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी लगभग हर गाँव के और ग्राम समूहों के अपने देवी-देवता हैं। हमारे अतीत में कई ऐसी महान विभूतियों ने इस धरती पर जन्म लिया, जिन्होंने लोक-कल्याण की भावना से देश और समाज के हित में अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया और लोक-देवता और लोक-देवी के रूप में जनता के दिलों पर हमेशा के लिए रच-बस गए। छत्तीसगढ़ के लोक देवता करिया धुरवा और उनकी पत्नी करिया धुरविन यानी राजकुमारी देवी कुंअर की जीवन गाथा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिन्हें महासमुंद जिले की तत्कालीन कौड़िया की जमींदारी रियासत में जनता के बीच और विशेष रूप से आदिवासी समाज में देवी-देवता के रूप में अपार प्रतिष्ठा मिली।

जब बरात जाय बर पोगरावन बइला गाड़ी..

सुशील भोले

जब ले सुष्टि उदरे हे, तब ले एकर नियमित संचालन खातिर नर अउ मादा के वैवाहिक-संबंध कोनो न कोनो रूप म होवत रहे हे. जइसे-जइसे समूह, परिवार संग शिक्षा अउ संस्कार के अंजोर म लोगन आवत गिन, तइसे-तइसे ए संबंध ह एक सुव्यवस्थित रूप लेवत गिस. आज हम एला अलग-अलग समाज अउ वर्ग म अलग-अलग नैंग-जोग अउ परंपरा के रूप म देखथन।

जिहाँ तक हमर छत्तीसगढ़ के बात हे, त इहाँ पहिली पाँच तेलिया माने पाँच दिन के बिहाव, तीन तेलिया माने तीन दिन के बिहाव देखे बर मिलत रिहिसे, जेन ह अब दू दिनिया ले एक दिनिया अउ अब तो एक जुवरिया घलो देखे बर मिल जाथे. जइसे-जइसे लोगन काम बुता अउ आने-आने रोजी रोजगार म बिपतियावत जावत हें, तइसे-तइसे बेरा-बखत म कमी आवत जावत हे, जे ह अइसन किसम के रीति रिवाज अउ परंपरा मन के परिवर्तन के रूप म घलो दिखत जावत हे।

इहाँ के मूल निवासी समाज म पैतृल बिहाव, जेमा लड़की ह अपन पसंद के लड़का के घर घुसर जावत रिहिसे, फेर वोला लड़का के राजी होए के बाद सामाजिक स्वीकृति मिल जावत रिहिसे. अइसने एक लमसेना बिहाव घलो होवय. एमा बिहाव के लाइक लड़का ल लड़की घर जा के एकाद-दू बछर रहि के अपन शारीरिक कार्यकुशलता के परिचय देना परय. जब लड़की वाले मन वोकर काम काज ले संतुष्ट हो जावँय, त फेर उँकर बिहाव कर दिए जाय. कोनो कोनो एला घरजिया अउ घरजन प्रथा घलो कहिथें. एक भगेली बिहाव के घलो परंपरा रिहिसे. एहा लड़का अउ लड़की के सहमति ले होवय. ए ह एक किसम के प्रेम बिहाव ही राहय. लड़का लड़की के घर वाले मन उँकर बिहाव खातिर राजी नइ होय म अइसन बिहाव होवय. एमा लड़की ह रतिहा म अपन घर ले भाग के प्रेमी के घर आ जावय, अउ वोकर छपरी के नीचे आके खड़ा हो जावय. तब लड़का ह एक

लोटा पानी धर के अपन छपरी म डारय, वो पानी ल लड़की ह अपन मुड़ी म ले लेवय. तब लड़का के महतारी सियान मन लड़की ल अपन घर भीतर ले जावँय. तहाँ ले गाँव के सियान मन लड़की के भगेली होय के सूचना देके उँकर बिहाव करवा देवयँ. इहाँ के कुछ समाज म गुराँवट बिहाव घलो देखे बर मिल जाथे. एमा लड़का अउ लड़की के आपस म अदला-बदली हो जाथे. माने एक घर के बेटी दूसर घर त वो घर के बेटी एकर घर।

बरात जाए के तो असली मजा रहय. तब बइला गाड़ी, भइँसा गाड़ी अउ सवारी गाड़ी. ये तीन किसम के विकल्प राहय बरात जाए खातिर. हमर मनके जुगाड़ राहय, कइसनो करके बइला गाड़ी के सवारी मिल जाय. काबर ते बइला मन भइँसा ले थोकन बनेच रेंगयँ. सवारी गाड़ी (कोनो-कोनो एला छाकड़ा गाड़ी घलो कहिथें.) घलो राहय, फेर वो ह एक किसम से दुल्हा बाबू खातिर

आरक्षित राहय. वोमा सिरिफ नैंग वाले मन ही दुल्हा के संग म बाइठयँ. तब बरात एक जुवरिया बेरा बरतिया भात खा के निकलन. दिन बुड़तही दुल्हन गाँव पहुँचय, त फेर परघनी के तैयारी चलया. बराती मन के असली मजा तो परघनीच म होथे. परघनी ठउर ले लेके जेवनास घर के पहुँचत ले गंडवा बाजा ल जगा-जगा छेक के नाचना. पहिली कतकों बरात म अखाड़ा वाले मन घलो जावँय, जे मन अपन शारीरिक कला के अद्भुत प्रदर्शन करँय. कोनो कोनो गाँव म अखाड़ा नइ राहय, ते मन दूसर गाँव के अखाड़ा वाले मन ल मान-गौन कर के लेगँय. कभू-कभू तो अखाड़ा के प्रदर्शन ह रात भर चल जावय. अब तो वो सब देखना दुर्लभ होगे हे. बिहाव के शुरू होवत ले मड़वा के झरत तक हर प्रसंग खातिर अलग-अलग गीत. वो सब ल सुरता करबे त लागथे, के हमर लोक साहित्य अउ परंपरा कतेक समृद्ध रिहिसे. चुलमाटी ले चालू होवय, तेन ह तेल चधी, माय मौरी, नहडोरी, बरात निकलनी, परघनी, भाँवर, बिदाई, डोला परघनी ले लेके कंकन मउर के छूटत अउ आखरी म मड़वा झर्रा के तरिया म सरोवत तक हर प्रसंग के गीत चलया।



फिर साथ आएंगे उद्धव और राज ?

आसान नहीं राह, कई शर्तें करनी होंगी पूरी



मुंबई। एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र के उद्योग और व्यवसाय गुजरात जा रहे हैं, उस वक्त अगर आपने (राज ठाकरे) विशेष किया होता, तो केंद्र में आज जो सरकार बैठी है, वह नहीं बैठी होती और केंद्र में महाराष्ट्र का हित समझने वाली सरकार हमने स्थापित की होती। उद्धव ने कहा कि पहले आप ये तय कर लें कि मैं महाराष्ट्र के हित से समझौता नहीं करूंगा, न ही ऐसे लोगों को अपने घर बुलाऊंगा, न उनके घर जाऊंगा, न मंच साझा करूंगा। ऐसे लोगों की आवभगत नहीं करूंगा। उनके साथ नहीं बैठूंगा।

फिर आप महाराष्ट्र हित की बात करें। बाकी रही बात झगड़े की, तो वैसे भी मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं था, लेकिन आज मैं सारे झगड़े खत्म करता हूँ।

राज के बयान से सुगबुगाहट तेज

दरअसल, महेश मांझरेकर के साथ एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अस्तित्व के सामने ये सब झगड़े छोटे नजर आते हैं, साथ में आना ये कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन सवाल इच्छा का है। इसके बाद सियासी हलकों में ये सवाल उठने लगा कि

महाराष्ट्र के दुश्मन को अपने घर में जगह न दें: संजय राउत

उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे ने कहा है कि अगर दोनों भाइयों के बीच कोई शिकायत है, तो मैं अपना अहंकार अलग रखूंगा और महाराष्ट्र के सर्वोत्तम हितों के लिए इसे (शिकायत) दूर करूंगा। जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भाई हैं और हमारे बीच कोई शिकायत नहीं है और अगर कोई है, तो मैं उसे दूर करूंगा। लेकिन, आपको महाराष्ट्र और शिवसेना (यूबीटी) के दुश्मन को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। अगर आप इस पर सहमत हैं, तो हम निश्चित रूप से बात करेंगे।



क्या उद्धव और राज ठाकरे साथ आ रहे हैं? उधर, राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे झगड़ों को खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने राज ठाकरे के सामने शर्त भी रखी है, उन्होंने कहा कि जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ होगा उसे घर बुलाकर खाना नहीं खिलाएंगे।

अनुराग कश्यप का मुंह काला करने पर 1 लाख इनाम की घोषणा

जयपुर। फिल्म अभिनेता और निर्देशक अनुराग कश्यप की ओर से ब्राह्मणों के खिलाफ टिप करने को लेकर विवाद गहरा गया है। कश्यप की ओर से ब्राह्मण समाज के विरुद्ध की गई टिप्पणी से समाज में भारी आक्रोश है। चाणक्य सेना ने घोषणा की है कि अनुराग कश्यप का जो भी व्यक्ति मुंह काला करेगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।



चाणक्य सेना, सर्व ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सेवा संघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, विश्व ब्राह्मण परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ की शनिवार को ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें देशभर से संगठनों के पदाधिकारी जुड़े। ब्राह्मण समाज के लोग शनिवार शाम बजाज नगर थाने पहुंचे और अनुराग के खिलाफ प्रदर्शन किया। विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने बताया कि अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराकर गिरफ्तार करने की मांग की। एफआइआर में बताया कि सोशल मीडिया पर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के खिलाफ अशोभनीय शब्द लिखे। इससे मन को गहरा आघात लगा है। थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन कर अनुराग के फोटो पर जूते मारकर विरोध जताया। साथ ही सरकार से सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले ऐसे सामाजिक तत्वों के लिए गैर जमानती अपराध का कानून बनाने की मांग की। इस अवसर पर परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेन्द्र भारद्वाज, युवा अध्यक्ष दीपेश मिश्रा आदि उपस्थित थे।

हिंदुओं को मिलने चाहिए हथियार : सुवेंदु अधिकारी

मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल के नेता विपक्ष का बयान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर शनिवार (19 अप्रैल, 2025) को 'सेव बंगाली हिंदू' नाम से एक रैली निकाली। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ग्राम रक्षा कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए और स्थानीय लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार मिलने चाहिए।



कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार दिए जाने चाहिए।

'हिंदुओं को अपने घरों से भागना पड़ेगा'

उन्होंने कहा, 'जब तक ममता बनर्जी और उनकी पुलिस बंगाल में मामलों को संभालती रहेंगी, हिंदुओं को अपने घरों से भागना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक निकायों को इस हिंसा का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।' सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार उन्हें मुर्शिदाबाद और अन्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोक रही है।

मुर्शिदाबाद और 24 परगना में 11 अप्रैल को हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। एक समुदाय के खिलाफ सुनियोजित हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हिंसा प्रभावित जिलों में स्थायी तौर पर बीएसएफ का कैंप लगना चाहिए। एक इंटरव्यू में सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'मेरे विचार से ग्राम रक्षा

मोदी के प्लान ने दिया चीन को झटका श्रीलंका में बढ़ेगा भारत का दबदबा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने की शुरुआत में (6 अप्रैल, 2025) तीन दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर गए थे। इस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा मामलों को लेकर कई समझौते हुए। इन समझौते की वजह से राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के घरेलू आलोचक इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यह संयोग नहीं था एमओयू पर हस्ताक्षर होने से ठीक



54 साल और 1 दिन पहले (5 अप्रैल, 1971) को दिसानायके की राजनीतिक पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) ने मातृभूमि या मृत्यु के नारे के साथ भारतीय विस्तार के खिलाफ श्रीलंका का पहला सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। जेवीपी मार्क्सवादी-लेनिनवादी के विचारों पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। ये पार्टी 1987-89 के दौरान कोलंबो में तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक और सशस्त्र विद्रोह में शामिल थी।

भारत ने अपनाई 'महासागर' पॉलिसी

कोलंबो के प्रति नई दिल्ली की रणनीति पीएम मोदी के दृष्टिकोण (महासागर) क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति को जाहिर करती है, जिसकी घोषणा उन्होंने 12 मार्च को मॉरीशस में की थी। महासागर दृष्टिकोण सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) नीति पर आधारित है।

श्रीलंका चीन के लिए इसलिए है महत्वपूर्ण

ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन भी श्रीलंका में अपना विस्तार करने की योजना बना रहा है। श्रीलंका चीन के लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्सर्स रणनीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

साल के अंत तक भारत आने की संभावना: मस्क

वाशिंगटन। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शनिवार



19 अप्रैल, 2025 को एक्स पर बताया कि वे साल के अंत तक भारत आने की योजना बना रहे हैं। इससे एक दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी, जिसे उन्होंने "सम्मान की बात" बताया। एलन मस्क ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी से बात करना सम्मानजनक था। मैं इस साल के आखिर में भारत दौरे के लिए उत्साहित हूँ।" दरअसल, पीएम मोदी और मस्क के बीच यह बातचीत टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्पेस रिसर्च और बाईलेटरल कोऑपरेशन पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025 को बताया कि उन्होंने एलन मस्क के साथ हाल ही में फोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

सुप्रीम कोर्ट पर बयान देकर फंसे दुबे!

अटॉर्नी जनरल के पास पहुंची चिट्ठी, अवमानना की कार्रवाई होगी

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश (CJ) संजीव खन्ना को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर अब कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल (AG) को पत्र लिखकर 'अवमानना की कार्यवाही' शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है।

कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति दें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार (19 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ



नड्डा ने कहा-भाजपा का कोई लेना-देना नहीं

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विवादास्पद बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है।

विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन पर एकशन की मांग उठने लगी है। बीजेपी सांसद सांसद के इस बयान के बाद कई विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी को घेरा है। हालांकि, बीजेपी ने इस बयान से दूरी बना ली है और कहा है कि ये उनका बयान है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से विपक्षी पार्टियों ने उन्हें जमकर निशाना बनाया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में बढ़ रहे धार्मिक तनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत अपनी सीमाएं लांघ रही है और अगर हर मुद्दे का हल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो फिर संसद और विधानसभाओं का कोई औचित्य नहीं बचता।

2050 तक एशिया पैसिफिक में घट जाएगी मुस्लिम आबादी

नई दिल्ली। प्यू रिसर्च सेंटर की 2050 की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम धर्म की आबादी एशिया पैसिफिक में कम हो जाएगी। हिंदू धर्म तीसरे स्थान पर होगा। प्यू रिसर्च सेंटर ने साल 2050 तक धर्म आधारित जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। इसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस्लाम वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ेगा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां मुस्लिम जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलेगी और वो है एशिया-पैसिफिक रिजन। एशिया-पैसिफिक रिजन में साल 2010 तक मुस्लिम आबादी 61.7% थी, जो 2050 तक घटकर 52.8% हो जाने का अनुमान है। यह बदलाव प्रजनन दर में गिरावट, शहरीकरण और धर्मांतरण जैसे सामाजिक-आर्थिक कारणों से होगा। वर्ष 2050 तक हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म होगा, जिसकी वैश्विक आबादी लगभग 1.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी।

आरसीबी ने पंजाब को 7 विकेट से हराया, कोहली का अर्धशतक



चंडीगढ़। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आईपीएल 2025 के 37वें मुकाबले में पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में आरसीबी ने 18.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। उसके लिए विराट कोहली ने दमदार प्रदर्शन किया।

विराट कोहली ने आरसीबी के लिए 54 गेंद का सामना करते हुए ना बाट 73 रन बनाए। उन्होंने इस पारी के दौरान 7 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 35 गेंद का सामना करते हुए 61 रन बनाए। उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। अंत में जितेश शर्मा 11 में बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान के साथ 157 रन बनाए। उसके लिए शशांक सिंह ने 31 रनों के नाबाद पारी खेली। मार्को जॉनसन ने नाबाद 25 रन बनाए। प्रियांशु आर्य ने 15 गेंद में 22 रन बनाए। प्रभसिमरन ने 17 गेंद में 33 रनों का योगदान दिया। इस दौरान आरसीबी की ओर से बॉलिंग करते हुए कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने दो-दो विकेट झटके। रोमारियो शेफर्ड को भी एक विकेट हाथ लगा।

मुंबई इंडियंस ने लिया बदला चेन्नई को 9 विकेट से हराया



रोहित शर्मा के 45 गेंदों में 76 और सूर्यकुमार यादव की 30 गेंदों में 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेटों से हरा दिया है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 175 रन बनाए थे। उनके लिए शिवम दुबे ने 50 और रवींद्र जडेजा ने 53 रनों की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह ने मुंबई के लिए दो विकेट लिए। मुंबई ने 176 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। रोहित-सूर्यकुमार ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 114 रनों की साझेदारी निभाई। इस जीत के साथ मुंबई ने इस सीजन में चेन्नई से चेपांक में मिली हार का बदला भी ले लिया है। मुंबई का इकलौता विकेट जडेजा ने हासिल किया।

EPFO 3.0 को लेकर बड़ी न्यूज़! अब एटीएम से ही निकलेगा पैसा

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है जिसके बाद पैसा निकालना और आसान हो जाएगा। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि ईपीएफओ का नया वर्जन अगल महीने यानी मई-जून से शुरू हो सकता है। इसके बाद करीब 9 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को इस अपडेट का फायदा मिलेगा। श्रम मंत्री का कहना है कि नए प्लेटफॉर्म पर डिजिटल करेक्शन, ऑटो क्लेम सेटलमेंट और एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रोसेस आसान और तेज होगा। यानी उसके बाद ईपीएफओ खाताधारकों को क्लेम के लिए न ही ऑफिस जाने की जरूरत होगी और न ही लंबा फॉर्म भरना पड़ेगा। मंडाविया ने बताया कि ईपीएफओ 3.0 का वर्जन से सर्विसेज काफी ज्यादा पहले की तुलना में आसान हो जाएंगी और इसे मजबूत आईटी सिस्टम के साथ लागू किया जाएगा।



निकालना और आसान हो जाएगा। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि ईपीएफओ का नया वर्जन अगल महीने यानी मई-जून से शुरू हो सकता है। इसके बाद करीब 9 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को इस अपडेट का फायदा मिलेगा। श्रम मंत्री का कहना है कि नए प्लेटफॉर्म पर डिजिटल करेक्शन, ऑटो क्लेम सेटलमेंट और एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रोसेस आसान और तेज होगा। यानी उसके बाद ईपीएफओ खाताधारकों को क्लेम के लिए न ही ऑफिस जाने की जरूरत होगी और न ही लंबा फॉर्म भरना पड़ेगा। मंडाविया ने बताया कि ईपीएफओ 3.0 का वर्जन से सर्विसेज काफी ज्यादा पहले की तुलना में आसान हो जाएंगी और इसे मजबूत आईटी सिस्टम के साथ लागू किया जाएगा।

पदार्पण करते ही रिकार्ड बुक में शामिल हुए 14 साल के वैभव



जयपुर। समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार (19 अप्रैल 2025) को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल डेब्यू के साथ ही इतिहास रच दिया है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे हैं। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर के खिलाफ 80 मीटर का छक्का मार दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपनी धमाकेदार शुरुआत से वैभव ने हर किसी को हैरान कर दिया और मैच के दौरान जबतक क्रीज पर रहे तबतक लगातार विपक्षी गेंदबाजों के ऊपर हमला जारी रखा। वैभव सूर्यवंशी से पहले नौ बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल के डेब्यू मैच में पहली बॉल पर छक्का मारा है।

पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले खिलाड़ी
रॉब क्वीनी: राजस्थान रॉयल्स
केवोन कूपर: राजस्थान रॉयल्स
आंद्रे रसेल: कोलकाता नाइट राइडर्स
कार्लोस ब्रैथवेट: दिल्ली डेयरडेविल्स
अनिकेत चौधरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर
जेवन सियरल्स: कोलकाता नाइट राइडर्स
सिद्धेश लाड: मुंबई इंडियंस
महेश तीक्ष्णा: चेन्नई सुपर किंग्स

वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगा पाकिस्तान

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बहुत बड़ा एलान करके बताया है कि वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए पाक टीम भारत नहीं जाएगी। बता दें कि वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन इसी साल भारतीय सरजमीं पर होने वाला है। महिला वर्ल्ड कप में कुल 8 टीम खेलेंगी, जो 29 सितंबर-26 अक्टूबर तक खेला जाएगा। भारत ना जाने का कारण देते हुए PCB का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई थी, उसी तरह पाकिस्तान की महिला टीम विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारत को हेकड़ी दिखाते हुए कहा, "जिस तरह भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने पाकिस्तान नहीं आया था और उसे न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने की अनुमति दी गई थी, उसी तरह पाक टीम के लिए जो भी न्यूट्रल वेन्यू चुना जाता है, टीम वहां खेलने के लिए तैयार रहेगी। जब कोई समझौता हो चुका हो, उसका पालन होना ही चाहिए।"



जिंदगीभर चलेगी इस इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, छह महीने में बनी टॉप सेलर

मुंबई। MG Windsor EV ने इंडिया में धमाल मचा दिया है। यह इलेक्ट्रिक कार अपने फीचर्स और रेंज की वजह से तो ग्राहकों को पसंद आई ही, साथ ही इसके साथ मिल रही बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी ने भी ग्राहकों को चिंतामुक्त कर दिया है। इसका नतीजा यह रहा है कि यह इंडिया की सबसे तेज बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। 6 महीने के भीतर इसे 20 हजार से ज्यादा लोगों ने खरीद लिया।



हालांकि, कार के लिए वारंटी सिर्फ 3 साल तक ही दी जा रही है।

Windsor EV रेंज

एमजी विंडसर ईवी की कीमत चुने गए वैरिएंट के आधार पर 15.01 लाख रुपए से लेकर 17.09 लाख रुपए दिल्ली में ओन रोड के बीच है। इलेक्ट्रिक कार एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस जैसे 3 अलग-अलग वैरिएंट में उपलब्ध है। विंडसर ईवी 38kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है और इसकी रेंज 331 किमी बताई गई है। मोटर आगे के पहियों को पावर देती है और पावर आउटपुट 134bhp/200Nm है। इसमें इको, इको+, नॉर्मल और स्पोर्ट जैसे ड्राइविंग मोड हैं। Windsor EV का मुकाबला Tata Nexon EV, Mahindra XUV400 और Hyundai Creta EV से है।

कंपनी विंडसर ईवी खरीदने वाले लोगों को लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे रही है। इसका मतलब है कि जब तक गाड़ी की लाफ रहेगी बैटरी खराब होने पर सुधार करा सकते हैं। हालांकि, यह वारंटी सिर्फ कार के पहले मालिक को मिलेगी। अगर कोई ग्राहक कार को किसी और को बेच देता है तो उस सेकंड ऑनर को 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी।

बजाज और टीवीएस को पछाड़ नंबर वन बनना ओला का लक्ष्य

मुंबई। इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री के मामले में पिछले एक-दो महीने से पिछड़ रही ओला इलेक्ट्रिक ने इस बार अप्रैल खत्म होने से पहले ही बड़ा दावा कर दिया है। कंपनी ने बताया कि वह इस महीने इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर बेचने के मामले में बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर से आगे निकल गई है। कंपनी का दावा है कि उसने अप्रैल में अब तक 11,330 यूनिट इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर बेच दिए हैं, जो इस महीने अब तक भारत में बेचे गए कुल इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स का 23% है।



के दावरे में है। ओला ने फरवरी में 28% बाजार हिस्सेदारी के साथ 25,000 इकाइयों की बिक्री का दावा किया था, लेकिन वाहन डेटा ने केवल 8,653 रजिस्टर्ड यूनिट दिखाई थीं।

ओला की बिक्री की तुलना कंपनियों से नहीं की जा सकती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर में फरवरी और मार्च के बैकलॉग शामिल हो सकते हैं। फरवरी में रिपोर्ट की गई बिक्री और सरकार के वाहन पोर्टल पर दर्ज रजिस्ट्रेशन के बीच विसंगतियों को लेकर कंपनी उद्योग मंत्रालय की जांच

पुणे स्थित फर्म ने 9,436 यूनिट बेचीं, जिससे 19% बाजार हिस्सेदारी हासिल हुई। यह मार्च से तेज गिरावट है, जब इसने 27% हिस्सेदारी के साथ 35,130 यूनिट बेचीं थीं। इस बीच, TVS मोटर ने अप्रैल में 10,335 यूनिट बेचकर 21% बाजार हिस्सेदारी हासिल करते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा किया। मार्च में कंपनी ने अपने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की 30,614 यूनिट बेचीं, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी 23% रही।

कांग्रेस का आरोप; सरकार पूरा चावल नहीं ले रही धान की इसलिए नीलामी

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार ने सदन में प्रदेश में 110 लाख मैट्रिक टन धान उत्पादित होने का आंकड़ा दिया है। सरकार ने इस वर्ष जो धान खरीदी किया है वह 154 लाख मैट्रिक टन से अधिक है। जब प्रदेश में इतना धान उत्पादित नहीं हुआ है, जितना खरीदी बताया जा रहा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए की 110 लाख मैट्रिक टन से ऊपर की जो 44 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है वह धान कहां से आया है?

पिछले वर्ष भी सरकार ने उत्पादन से लगभग 10 लाख मैट्रिक टन धान अधिक खरीदा था, विधानसभा में सरकार ने बताया था कि पिछले वर्ष धान का उत्पादन 100.3 लाख मैट्रिक टन हुआ था तथा सरकार ने 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का दावा किया था जब उत्पादन कम था तो खरीदी ज्यादा कैसे हो सकती है?



सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार इस वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान को खुले बाजार में बेचने जा रही है। लगभग इतना ही धान उत्पादन से अधिक है जिसे सरकार ने खरीदा है। मतलब किसानों के पैदा किये धान से 44 लाख मैट्रिक टन धान अधिक खरीदा

गया जिसे खुले बाजार में बेचना पड़ रहा है। यह राज्य के खजाने पर डकैती है तथा संगठित भ्रष्टाचार है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदी के नाम से भाजपा सरकार ने 13,000 करोड़ से अधिक की गड़बड़ियां घोटाला किया है, जिसका भांडा रोज फूट रहा है।

डबल इंजिन सरकार फेल, बस्तर की जनता पानी के लिए तरस रही : बैज

शहर सत्ता/रायपुर। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रायपुर में मिडिया को बयान जारी करते हुए साय सुशासन और बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर तंज कसा है। बैज मिडिया से बोले; डबल इंजन सरकार फेल हो गई है और बस्तर की जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है, केन्द्र में भी भाजपा सरकार है तो फिर भी इंद्रावती नदी जल बंटवारा क्यों नहीं सुलझा। श्री बैज के मुताबिक आज बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, पिछले कई दिनों से इंद्रावती से सटे किसान इंद्रावती नदी में पानी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, परंतु डबल इंजन की सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर इंद्रावती नदी में पानी के लिए उड़ीसा सरकार से चर्चा तक नहीं कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता का ही नतीजा है, बस्तर के लोग बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी को तिल-तिल मारता हुआ देखने को मजबूर है। पीसीसी चीफ का कहना है कि साय सरकार ने इंद्रावती नदी का पानी रोकने कोई पहल नहीं की जिसके चलते केन्द्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय विकास जल अभिकरण और तेलंगाना सरकार 148 टीएमसी पानी छत्तीसगढ़ के बस्तर को देने की बजाए तेलंगाना सरकार को देने की बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस बस्तरवासियों को सरकार के हाल पर नहीं छोड़ सकती। हम बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती को सूखते नहीं देख सकते। सरकार शीघ्र उड़ीसा सरकार के बात नहीं करती इस समस्या का समाधान नहीं करती तो हम आंदोलन को मजबूर होंगे।



साय सरकार को लगेगी महिलाओं की हाथ : जरिता

शहर सत्ता/रायपुर। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता लैतफलांग ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ित को ही प्रताड़ित करने का चलन है जिसके चलते अपराधी बेखौफ और अपराध बेलगाम हो चुका है।

पूर्व में भिलाई डीपीएस में मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था, तब भी प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार पर अनुचित दबाव बनाकर मामले पर लीपापोती कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस केवल कमीशन कोरियर भ्रष्टाचार में है जिसके चलते अपराध अनियंत्रित हो गया है।

खास तौर पर प्रदेश में महिलाएं बेहद असुरक्षित हो गई हैं छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आने के बाद से औसतन प्रतिदिन 8 से 9 दुराचार की घटनाएं प्रदेश की महिलाओं के साथ घट रही हैं, अर्थात लगभग हर 3 घंटे में एक न एक महिला या बच्ची दुष्कर्म की



प्रदेश में महिलाएं हैं असुरक्षित

शिकार हो रही है लेकिन सरकार हाथ पर हाथ भर बैठी है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता लैतफलांग ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की समृद्धि के लिए शानदार काम किया। अपराध नियंत्रित थे और कोई भी अपराधी पुलिस के गिरफ्त के बाहर नहीं था। बस्तर में दुर्गा और दंतेश्वरी बटालियन जैसे महिला कमाण्डो तैयार किया, डीआरजी में महिलाओं की भर्ती की।

गोठानो के माध्यम से महिला समूहों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया, डेनेक्स जैसे बॉन्ड की स्थापना करके महिलाओं के भीतर उद्यमिता के साथ सहकार की भावना का विकास और सुरक्षा की भावना जागृत की लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पीछे धकेला जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से प्रदेश में भय का माहौल है।

कांग्रेस बोली; हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट के नाम पर लूट रही सरकार



शहर सत्ता/रायपुर। पुराने वाहनों में हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट बदलने में प्रक्रियागत त्रुटि, असुविधा और अनिवार्यता को लेकर की जा रही सख्ती का कड़ा प्रतिवाद करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि लगभग 50 से 70 रुपए के औषत लागत के नंबर प्लेट के लिए दस गुना अधिक राशि की जबरिया वसूली किया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में मुनाफाखोरी करके जनता के जेब में डकैती की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में हजारों कंपनियां हैं जो नए हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट बनाने का काम कफियाती दर पर कर सकती है लेकिन भाजपा की कमीशनखोर सरकार के द्वारा दिल्ली और हरियाणा की केवल दो

ही कंपनियों को उपकृत करने की जिद ने लाखों लोगों को कतार में खड़ा होने मजबूर कर दिया है। परिवहन विभाग की अक्षमता और सिस्टम में खामी की सजा भी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। 1 अप्रैल 2025 से इस मामले में चालानी कार्यवाही शुरू हो गई है, 500 से 10 हजार तक भारी भरकम जुर्माना वसूली वाहन मालिकों पर अत्याचार है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अप्रैल 2019 से पहले के लाखों वाहनों में से अधिसंख्यक वाहनों में अभी भी है पुराने नंबर प्लेट लगे हैं, जिन्हें बदलने

में सुविधाजनक प्रक्रिया मुहैया कराने के बजाय सख्ती से जुर्माना वसूली ही इस निर्दयी सरकार का फोकस है। आरटीओ ने बिना हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट के वाहनों के फिटनेस जांच नहीं करने का फरमान जारी कर दिया है। जब ऐसे नंबर प्लेट स्थानीय स्तर पर और भी कंपनियां बन सकती हैं, कम कीमत पर बना सकती हैं अधिक तत्परता से बना सकती हैं फिर केवल दो कंपनियों पर निर्भरता क्यों? गुणवत्ताहीन नंबर प्लेट जिसकी लागत 50 रुपए भी नहीं होगी, दुपहिया वाहनों के लिए 483 रुपए, निजी कार के 656 इसी तरह तिपहिया और कमर्शियल वाहनों और भी अधिक वसूली की जा रही है।

कांग्रेस विधायक के PSO ने खुद को मारी गोली...मौत



शहर सत्ता/बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा से कांग्रेस विधायक इंद्र साव के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) ने रविवार को खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक महीने पहले ही लव मैरिज की थी। वारदात भाटापारा थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार, घटना विधायक के घर के सामने वाले घर में हुई। मृत PSO का नाम डिगेश्वर गागड़ा है। वह कांग्रेस विधायक इंद्र साव के निजी सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे। खुद पर 3 बार फायरिंग की है।

ऐसे हुई जानलेवा वारदात

दरअसल, विधायक इंद्र साव के घर सामने ही डिगेश्वर गागड़ा का क्वार्टर है। रविवार दोपहर को गागड़ा अपने घर पर थे। साढ़े 3 बजे के करीब अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार

ली। गोली लगते ही PSO खून से लहलुहान होकर जमीन पर गिर गए।

फायरिंग की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, तब तक PSO गागड़ा की मौत हो चुकी थी। लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी। भाटापारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

विधायक बोले- बिल्कुल सामान्य था डिगेश्वर

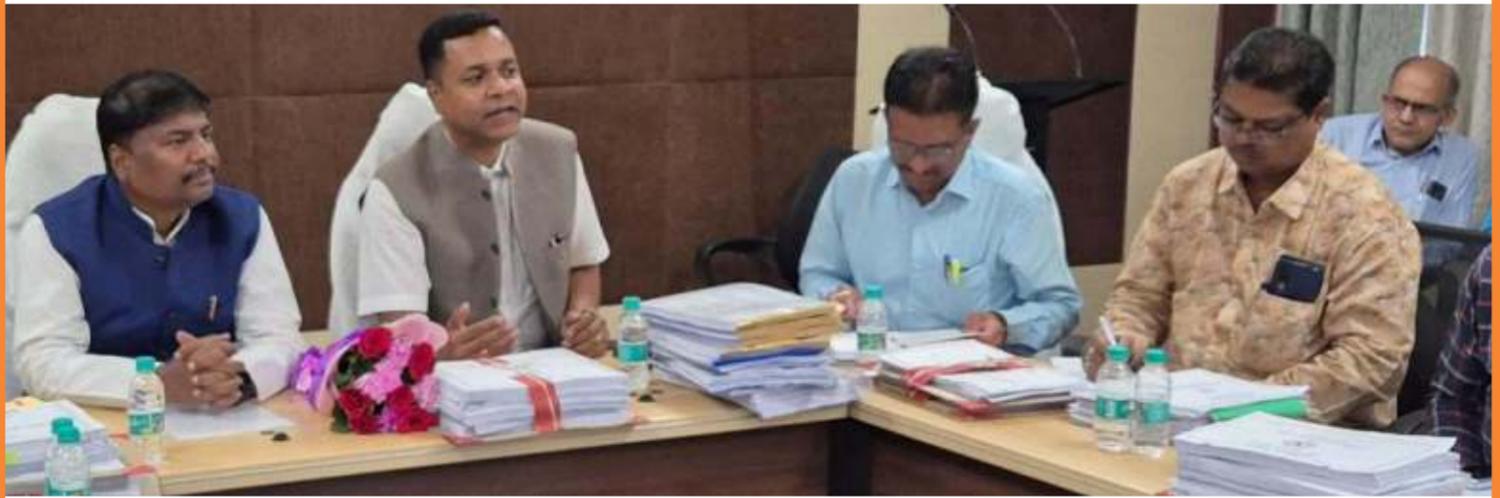
भाटापारा विधायक इंद्र साव ने बताया कि डिगेश्वर चुनाव के बाद से उनकी सुरक्षा में तैनात था। उन्होंने एक माह पहले ही प्रेम विवाह किया था। डिगेश्वर सामान्य रूप से रह रहा था। उसके व्यवहार में कोई असामान्यता नहीं थी। पता नहीं क्यों इस तरह की आत्मघाती कदम उठाया।



रायपुर IG ने ली पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की बैठक

शहर सत्ता/रायपुर। IG रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने पुलिस कार्रवाई के बाद भी कोर्ट से बड़े ही आराम से छूट जा रहे अपराधियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों से रूबरू हुए। उन्होंने पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराधियों पर दोषसिद्धी का प्रतिशत बढ़ाये जाने के लिए निर्देशित किया। अभियोजन अधिकारियों को न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व प्रकरणों की नवीन अपराधिक कानूनों के तहत समीक्षा की जाकर कमियों को दूर करते हुये न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किये गये प्रकरणों की समीक्षा की जाकर गुण दोषों के आधार पर सक्षम न्यायालय के समक्ष निश्चित समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु ताकीद की। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा द्वारा सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में दो पालियों में बैठक आयोजित की गई। प्रथम पाली में उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिले के राजपत्रित अधिकारी, उप संचालक अभियोजन, शासकीय अभिभाषक, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं सहायक शासकीय अभिभाषक की बैठक ली गई। पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में बस्तर रेंज में तैनात DRG/STF/CoBRA/CRPF/BSF/ITBP/CAF/Bastar Fighters व अन्य सुरक्षा बल सदस्यों द्वारा मजबूत मनोबल एवं स्पष्ट लक्ष्य के साथ बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा व विकास हेतु समर्पित होकर कार्य किया जा रहा है।

सप्ताहभर में होगी टेंडर में फर्जी जानकारी देने वाले 108 ठेकेदारों पर कार्रवाई



शहर सत्ता/रायपुर। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज शिवनाथ भवन, अटल नगर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता सहित कार्यपालन अभियंता स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री ने बैठक में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल संसाधन मंत्री श्री कश्यप ने निर्देशों के बावजूद

• विभागीय अफसरों को दिए कार्रवाई के सख्त निर्देश

टेंडर प्रक्रिया में फर्जी जानकारी देकर भाग लेने वाले करीब 108 ठेकेदार जिनकी पहचान कर ली है। उन सभी पर एक सप्ताह के भीतर उनकी ईएमडी राजसात करने के साथ ही उन्हें एक वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश

दिए। मंत्री श्री कश्यप ने प्रमुख अभियंता जल संसाधन को इस कार्रवाई का प्रतिवेदन देने के भी निर्देश दिए।

मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में 100 दिनों के भीतर सभी लंबित निविदाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराए जाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन की समय-सीमा को ध्यान में रखने की विशेष हिदायत दी।

बेटी अनुष्का की छठी में महतारी वंदन योजना से मनाई गई खुशियां



शहर सत्ता/रायपुर। जंगलों से घिरे कोरबा जिले के लेमरू ब्लॉक के घोधीबहरा गांव की श्रीमती दिलेशरी मंझुवार के घर हाल ही में खुशियों की लहर दौड़ गई। बेटी अनुष्का की छठी का आयोजन ऐसे समय हुआ, जब यह परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। लेकिन इन खुशियों के पीछे एक मजबूत सहारा बनी छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना, जिसके तहत श्रीमती दिलेशरी को हर महीने एक हजार की आर्थिक मदद मिल रही है।

गर्भावस्था के दौरान श्रीमती दिलेशरी को कई तरह की चिंताएं सताती थीं। घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि बच्चे के जन्म के बाद कोई खास आयोजन कर सकें। लेकिन जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई, तो श्रीमती दिलेशरी ने भी आवेदन किया। योजना का

लाभ मिलना शुरू हुआ और गर्भावस्था के दौरान यह राशि उनके लिए राहत बन गई। बेटी अनुष्का के जन्म के बाद जब छठी का समय आया, तो खाते में जमा योजना की राशि ने उनकी सारी चिंता दूर कर दी। श्रीमती दिलेशरी ने खुशी-खुशी छठी का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए किसी से उधार नहीं लेना पड़ा, न ही किसी से मदद मांगनी पड़ी। मजदूरी पर आधारित आय वाले इस परिवार के लिए यह योजना अब केवल एक सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया कदम है। श्रीमती दिलेशरी अब घर से लगे जमीन को समतल कर खेत बनाना चाहती हैं और इसके लिए भी योजना की राशि बचा रही हैं। "महतारी वंदन योजना हमारे जैसे गरीब परिवारों के लिए जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनकर आई है, श्रीमती दिलेशरी कहती हैं। यह योजना हमें आत्मसम्मान के साथ जीने का हक देती है। जरूरत के समय अब हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। राज्य सरकार की यह योजना न सिर्फ आर्थिक सहायता का माध्यम बन रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना भी जगा रही है।

पीएम फसल बीमा योजना में छग को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि

रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहला - मानपुर- चौकी और सक्ति को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कृषि के करकमलों यह सम्मान आज छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से संयुक्त संचालक बी.के. मिश्रा एवं उपसंचालक उद्यानिकी नीरज शाह ने प्राप्त किया। मोहला-मानपुर-चौकी जिले की कलेक्टर श्रीमती तूलिका प्रजापति एवं सक्ति जिले के कलेक्टर श्री टोपनो ने बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सम्मान राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की

वन मंत्री केदार ने किया जामगांव में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण



शहर सत्ता/रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड अंतर्गत जामगांव (एम) में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद विजय बघेल, जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधिगण और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि यह केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से 110 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही है। इस प्रसंस्करण इकाई से क्षेत्रीय रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। वन मंत्री केदार कश्यप ने निरीक्षण के दौरान लघु वनोपजों के संग्रहण, मिलेट्स फसलों के प्रसंस्करण और वितरण कार्यों का बारीकी से

अवलोकन किया। उन्होंने गोदामों में संग्रहित वनोपजों का जायजा लेते हुए अपूर्ण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द स्थानीय लोगों को इस परियोजना का लाभ मिल सके।

श्री श्री कश्यप ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। इस अवसर पर प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज अनिल साहू, डीएफओ चंद्रशेखर परदेशी, एसडीएम लवकेश ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कोतरलिया स्टेशन यार्ड में अंतिम चरण में चौथी रेल लाइन परियोजना

शहर सत्ता/रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिलासपुर-झारसुगुड़ा रेलखंड पर स्थित कोतरलिया स्टेशन पर वर्तमान में चौथी रेल लाइन परियोजना के तहत व्यापक नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य तीव्र गति से जारी है।

यह कार्य 11 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक

पूर्वनिर्धारित अवधि में किया जा रहा है एवं यह लगभग 2100 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन 206 किलोमीटर लंबी बिलासपुर - झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेल परिचालन की क्षमता में वृद्धि, समयबद्धता में सुधार और



यात्री सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाना है। कोतरलिया स्टेशन पर इस दौरान व्यापक स्टेशन एवं यार्ड मॉडिफिकेशन कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैक, सिग्नलिंग और ओवरहेड इन्फ्रस्ट्रक्चर (ओएचई) से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।

इसी प्रकार रेल विद्युतीकरण (ओएचई) से जुड़े

कार्यों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कार्य के दौरान हाइड्रॉ मशीन, जेसीबी, टावर वैन सहित अन्य आधुनिक मशीनों तथा इस कार्य के विशेषज्ञ अधिकारी, इंजिनियर, कर्मचारी एवं श्रमिकों ने रेल विद्युतीकरण (ओएचई) कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

छॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की घिनौनी सच्चाई

मेहनत किसी की, नाम और पैसा किसी और का

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के चंद लोगों के लिए एक कहावत फिट बैठती है... गधे खीर खा रहे। फिल्म इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई सामने आ रही है। जिसमें फिल्म डायरेक्शन, क्रिएटिव डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर, एडिटर, लिटरिक्स राइटर जैसे फिल्म में जान डालने वाले किरदारों की मेहनत को अपना बताकर तारीफ और अवार्ड जुटाने वाले नाकाबिलों की अच्छी-खासी तादात हो गई है। शहर सत्ता के कला समीक्षक ने ऐसे नकली चेहरों को बेनकाब करने वाली हैरतअंगेज खबर का पर्दाफाश किया है। बताते हैं कि अपनी तरक्की के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज का स्याह चेहरों की इस करतूत को अंदरूनी अव्यवस्था, कलाकारों के शोषण और गलत क्रेडिट सिस्टम से शाह मिल रही है। शहर सत्ता की खबर को पुख्ता करते हैं रायपुर के अनुभवी साउंड इंजीनियर और बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोड्यूसर आशीष रॉबिन्सन। बता दें कि रॉबिन्सन पिछले 20 वर्षों से देशभर में म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और 2018 से छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं।

आशीष का कहना है, "यहाँ पोस्ट-प्रोडक्शन पूरी तरह अव्यवस्थित है। कलाकारों को न सम्मान मिलता है, न समय पर मेहनताना। तुरंत यह कि कई दफे तो दूसरों की मेहनत को खुद की बताकर उसमें अपना नाम डाला जाता है। कई बार तो 1 लाख के प्रोजेक्ट का पैमेंट 5-6 महीने तक टुकड़ों में दिया जाता है।" वे आगे बताते हैं, "₹20,000 से ₹1.5 लाख के बजट में पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर एक हफ्ते में माँगा जाता है। और ऊपर से कहा जाता है, जुगाड़ हो गया है!"

रॉबिन्सन के मुताबिक उन्होंने 'तही मोर सोना', 'गांव के जीरो शेर मा हीरो', 'कुरुक्षेत्र', 'रुद्र', 'रक्षणम', 'मोह अउ माया' जैसी फिल्मों पर काम किया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म 'जानकी' और 'बली' के मोशन पोस्टर के लिए म्यूजिक भी बनाया, लेकिन उन्हें ना पैसे मिले ना क्रेडिट (नाम) दिया गया। उनकी मेहनत का सारा श्रेय भी प्रोडक्शन ने किसी और को दे दिया।

इस स्थिति को और गंभीर बनाता है इंडस्ट्री का एक और अनोखा चलन, जो मेहनत करने वालों को चौककर रख देगा। फिल्म को डायरेक्टर करता कोई और है मगर नाम प्रोड्यूसर लाने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। कई फिल्मों में असली डायरेक्टर वो होता है जो शूटिंग, प्लानिंग और टीम को संभालता है, लेकिन स्क्रीन पर डायरेक्टर का नाम उसी व्यक्ति का होता है जो फाइनेंसर या प्रोड्यूसर खोजकर ले आता है। इससे फिल्म निर्माण की प्रक्रिया और क्रिएटिव सम्मान दोनों का ही बेहद घटिया तरीके से इंडस्ट्रीज के बनावटी और जुगाड़ टाइप लोग मखौल उड़ा रहे हैं।

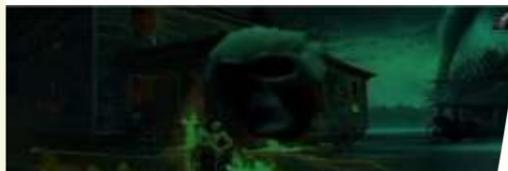
काम किसी का नाम और अवॉर्ड किसी को

सिस्टम से व्यथित आशिश का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि कलाकार सिर्फ भावुक नहीं, प्रोफेशनल बनें। अपने हक के लिए खड़े रहें, वे सलाह देते हैं। निष्कर्ष यही है, जब तक इंडस्ट्री के लोग खुद एकजुट होकर सिस्टम को सुधारने का बीड़ा नहीं उठाएंगे, तब तक बदलाव मुश्किल है। सुधार की शुरुआत हमें खुद करनी होगी।

आगामी फिल्म 'जानकी' और

बलि है इसका उदाहरण

छॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज की कड़वी हकीकत का एक नहीं दो नमूना (उदाहरण) है आने वाली फिल्म 'जानकी' और 'बलि'। इन दोनों ही फिल्मों में 'मोशन पोस्टर' के लिए म्यूजिक देने वाले की मेहनत को नजरअंदाज कर किसी दूसरे को उसका श्रेय और नाम दे दिया गया है। इसका पुख्ता साबुत है दोनों ही फिल्मों का टीजर जिसमें मेहनत थी आशीष रॉबिन्सन की और नाम दर्शाया गया है मनोहर यादव का। छालीवुड में चल रहे इस अनूठे शोषण का एक और दुखदायी पहलु है कि आशीष को नाम तो दूर अब तक उसका मेहनताना ही नहीं मिला है।



A FILM "BALI" COMING SOON..
DIRECTED BY "GANGA SAGAR PANDA"

बली फिल्म के निर्देशक का कहना है कि पुरे म्यूजिक का 20% ही रखा बाकि कहीं और से म्यूजिक करवाया गया है। रही बात पैसे की तो मैं बात करता हूँ देखता हूँ कि क्या और कितना देना है। उनको हम दे देंगे, लेकिन उनकी मेहनत के बदले दूसरे के नाम को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

- गंगासागर पंडा, निर्देशक 'बलि' फिल्म

शहरसत्ता के
कला समीक्षक
पूरन किरी
की प्रस्तुति

छालीवुड के कथित विद्वानों और नामचीन हस्तियों का एक विकृत चेहरा भी सोशल मिडिया में इन दिनों खासी चर्चा बटोर रहा है। गीत लेखन और साहित्यकार का दर्जा हासिल छालीवुड का यह शख्स एक धर्म विशेष को भेदी और अश्लील गालियां अपने फेसबुक अकाउंट से देते कुख्यात हो गया है। उसकी सड़क छाप गालियां और टपोरियों जैसी टिप्पणी से प्रशंसक भी खफा हैं और इंडस्ट्रीज के सम्मानित नाम वाले भी।

किसी अन्य धर्म, संस्कार और परंपरा को मां की गालियां देने वाले चर्चित गीतकार और स्वयं को साहित्यकार कहने वाले नवल दास मानीकपुरी हैं। चौकिए नहीं ऐसे ही एक और बदजुबान शख्सियतों में शुमार हैं छालीवुड के कथित कामयाब फिल्म निर्माता हैं मोहित साहू। 'एन माही फिल्म' प्रोडक्शन के कर्ता-धर्ता के खाते में सफल फ़िल्में भी बनीं हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सम्मान, परिधान और परंपरा के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही अगर महज उनकी फिल्म नहीं चली तो दर्शकों से बदजुबानी करने लगे तो फिर छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू, सादगी और सांस्कृतिक विरासत कौन संहालेगा?

छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दर्शकों, प्रशंसकों के कान में ज़हर घोलते शब्द और साहित्यकार की 'टपोरी' भाषा से आज छालीवुड एक शर्मनाक विवाद में है। चर्चित गीतकार और स्वयं को साहित्यकार कहने वाले नवल दास मानीकपुरी पर सोशल मीडिया पर अशोभनीय भाषा और एक विशेष समुदाय के खिलाफ भेदी गालियों का प्रयोग करने का गंभीर आरोप लग रहा है।

"जब शब्द ही हथियार हैं, तो ज़हर क्यों बोते हो?"

नवल दास, जिन्होंने कई हिट एल्बम और फिल्मों के गीत लिखे हैं, वे अचानक सोशल मीडिया पर एक टपोरी भाषा शैली में उतर आए। न केवल आम दर्शकों बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से में इससे नाराजगी फैल गई है। लोग सवाल कर रहे हैं - क्या अब छत्तीसगढ़ी साहित्य और सिनेमा के नाम पर गाली-गलौच बिकेगा?

फिल्म पिट गई तो भड़ास दर्शकों पर निकाला

कुछ महीने पहले बड़े प्रोडक्शन हाउस में शामिल 'एन माही फिल्म' की छत्तीसगढ़ी फिल्म रिलीज हुई। जब फिल्म नहीं चली, तो निर्माता ने खुलेआम दर्शकों को गालियाँ दीं, धमकियाँ दीं। कुछ पोस्ट डिलीट कर दिए गए, लेकिन कई अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मामला महज इतना है कि किसी दर्शक और यूट्यूबर ने सोशल मिडिया में इस प्रोडक्शन की एक फिल्म के बुरी तरह असफलता पर सामान्य टिप्पणी किया था बस फिर क्या था फिल्म निर्माता मोहित साहू ने सोशल मिडिया को ही सड़क छाप गालियों का गुलिस्ता बना डाला था। जरूरत है सफाई की, सिर्फ सिनेमा नहीं सोच भी साफ होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत खुद आत्ममंथन करे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अभद्रता को बढ़ावा देना बंद करें और जो कलाकार अपने शब्दों से समाज को दिशा देने की ताकत रखते हैं, उन्हें अपनी जुबान का सम्मान आईंदा के लिए रखना होगा।

गाली-गलौच और
नफ़रत की जुबान:
छत्तीसगढ़ी सिनेमा
को कौन ले डूबेगा?

अमलेश नागेश की आखिरी कोशिश 'गुड़िया- 2'

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब शख्सियतों की फेहरिस्त में अमलेश नागेश का नाम है। उन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में उफान पर थीं। खासकर प्रणव झा निर्देशित 'डार्लिंग प्यार झुकता नहीं' जैसी फिल्मों में सेकंड लीड से शुरू हुआ उनका ये सफर, निर्देशक सतीश जैन की फिल्म 'ले शुरू होंगे मया के कहानी' में लीड हीरो बनने तक पहुँचा, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सबको चौंका दिया।

इसके बाद 'गुड़िया', जिसमें निर्देशन की बागडोर मनीष मानीकपुरी के हाथ में थी और क्रिएटिव डायरेक्शन पूरन किरी थे। फिल्म ने भी ठीक-ठाक कारोबार किया। निर्माता मोहित साहू को इस फिल्म ने लगत से चार गुना कमाई करके दी।

इसी सफलता से प्रेरित होकर मोहित साहू ने अमलेश की लिखी और निर्देशित फिल्म 'हॉडा' बनाई। हालांकि फिल्म ने पहले हफ्ते में रिकॉर्ड कलेक्शन किया, लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म ढलान पर आ गई। इसके बाद आई भारती वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म 'डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2' और प्रणव झा द्वारा निर्देशित 'टीना टपपर' दोनों ही फिल्मों दर्शकों का भरोसा नहीं जीत पाई। रिलीज के दौरान टीम ने खूब प्रचार किया, यहां तक कि 'जाती कार्ड' तक खेला गया, मगर फिर भी थिएटर खाली रहे।



अब नजरें टिकी हैं 'गुड़िया 2' पर अमलेश नागेश की इस फिल्म को लेकर फैंस में हलचल तो है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी गूँज रही है, क्या ये अमलेश नागेश की आखिरी फिल्म होगी? इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि हालिया फ्लॉप्स की सबसे बड़ी वजह है गलत स्क्रिप्ट और कमजोर निर्देशन का चयन। पहले की तरह दर्शकों का भरोसा फिल्मों में नजर नहीं आता।

इतना ही नहीं, 'भैरा कका' के नाम से यूट्यूब पर राज करने वाले अमलेश का डिजिटल ग्राफ भी अब गिरता दिख रहा है। पहले जहां उनके वीडियोज लाखों व्यूज बटोरते थे, अब वो क्रेज भी धीरे-धीरे फीका पड़ता जा रहा है। अब देखना ये है कि 'गुड़िया 2' क्या अमलेश नागेश के करियर को एक नई दिशा दे पाएगी या ये फिल्म होगी उनके सुनहरे करियर का अंतिम अध्याय? यह शहर सत्ता नहीं बोल रहा बल्कि खुद अमलेश नागेश ने सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा बयान दिया है।

**MBA छोड़ा
खेती में सफल**

छत्तीसगढ़ का 'अमरूद वाला' बना करोड़पति किसान

**तकनीक से बदली
किसानी की तस्वीर**

कबीर के फार्म में आधुनिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा है। स्मार्ट डिवाइसेज से यह तय किया जाता है कि पौधों को कितनी पानी की जरूरत है और कितनी जमीन में नमी मौजूद है। हर एक पौधे की निगरानी डिजिटल डेटा से होती है।

उत्पादन और बाजार की बात

- एक एकड़ में सालाना 20-25 टन अमरूद का उत्पादन।
- दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया तक अमरूद की जबरदस्त डिमांड।
- एक्सपोर्ट भी होता है लेकिन कंपनियों के जरिए।

रोज़गार भी बना मिसाल

चार अलग-अलग लोकेशनों पर फैले 120 एकड़ के फार्म में साल भर करीब 200 लोग काम करते हैं। सीजन में ये संख्या 450 तक पहुंच जाती है। अमरूद की ग्रेडिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी टीम लगती है।

'अमरूद वाला' क्यों बना आइकॉन?

कबीर का मानना है कि खेती सिर्फ मिट्टी से नहीं, सोच से भी होती है। सही इनपुट, मार्केट की समझ और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल अगर हो जाए, तो खेती किसी कॉरपोरेट बिजनेस से कम नहीं।



“विदेश से लौटने के बाद 6 एकड़ में अमरूद की खेती हो रही थी। धीरे-धीरे 6 एकड़ के बाद 10 एकड़ 25 एकड़ 40 एकड़ इस तरह से पिछले 10 सालों में 120 एकड़ क्षेत्र में अमरूद की खेती कर रहे हैं। उसे समय अमरूद नया-नया आया था कोई भी नया चीज लॉन्च होता है तो वह उस समय पिक पर होता है। जिसकी शुरुआत नीचे से होती है और धीरे-धीरे ऊपर जाता है। एक टाइम के बाद मैच्योर हो जाता है। अमरूद की खेती आज पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है। नई टेक्नोलॉजी और नई वैरायटी जितनी इस जगह पर लगाई जानी थी उतना काफी कुछ हो गया है। पहले की तुलना में अधिकांश किसान अमरूद की खेती कर रहे हैं। अमरूद की खेती का सफर 10 सालों में पूरा हुआ है।

- कबीर चंद्राकर, युवा किसान

रायपुर। जब ज्यादातर लोग एमबीए के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर रुख करते हैं, रायपुर के कबीर चंद्राकर ने उल्टा रास्ता चुना — और आज वही रास्ता लाखों के लिए मिसाल बन चुका है। कॉरपोरेट फाइनेंस में एमबीए करने के बाद कबीर ने खेती को पेशा बनाया और उसे इतने स्मार्ट ढंग से आगे बढ़ाया कि वे छत्तीसगढ़ के सबसे सफल युवा किसानों में गिने जाते हैं।

कहानी की शुरुआत: दो रास्ते, एक फैसला
साल 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर (UK) से एमबीए की डिग्री लेने के बाद कबीर के पास दो ऑप्शन थे — विदेश में रहकर नौकरी करें या अपने गांव लौटकर खेती में कुछ नया करें। कबीर ने दूसरा रास्ता चुना। इस फैसले की बुनियाद थी — कुछ अलग करना, कुछ अपना बनाना।

पिता से विरासत, बेटे ने बनाई पहचान
कबीर के पिता सालों से अमरूद की पारंपरिक खेती कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 6 एकड़ जमीन तक सीमित। कबीर ने सबसे

पहले खेती की लागत को समझा और उसे कम करने के तरीके खोजे। उन्होंने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम का फायदा उठाकर लोन और सब्सिडी ली और खेती का रकबा बढ़ाकर पहले 10 एकड़ और आज 120 एकड़ पहुंचा दिया।

खेती में इनोवेशन से बनाई कमाई की राह
अमरूद की पैकिंग के लिए जरूरी 'फोम नेट' गुजरात से आता था, जिसकी लागत ₹2.50 प्रति पीस पड़ती थी। कबीर ने रिसर्च कर पाया कि यही नेट ताइवान और चीन से मंगवाया जाए तो सिर्फ ₹0.60 में मिल सकता है। उन्होंने सीधे विदेश से

10 लाख पीस का ऑर्डर देकर लागत को भारी स्तर पर कम किया।

क्यों चुनी अमरूद की खेती?

कबीर के मुताबिक, बाजार में जो नई चीज होती है उसकी डिमांड और वैल्यू दोनों ज्यादा होती है। सब्जी की खेती की तुलना में अमरूद की खेती सस्ती, टिकाऊ और लॉन्ग-टर्म में फायदेमंद साबित हुई। उन्होंने VNR बीही और पिक ताइवान जैसी हाई क्वालिटी किस्मों पर फोकस किया।

रायपुर सेंट्रल जेल बना सुधार और संवेदना का केन्द्र

अब कैदी सीख रहे जिंदगी के असली मायने



रायपुर। जेल का नाम सुनते ही जहन में एक सख्त और सजा देने वाली व्यवस्था की तस्वीर उभरती है, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल इस पारंपरिक सोच को तोड़ने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है।

अब यह जेल केवल अपराधियों को दंडित करने की जगह नहीं, बल्कि उन्हें इंसानियत, संवेदनशीलता और राष्ट्र प्रेम से जोड़ने वाली एक सुधारात्मक पाठशाला बन चुका है।

थियेटर नहीं, यह अब बदलाव का मंच है

हाल ही में जेल में एक खास पहल की गई, जिसमें बंदियों को बड़े पर्दे पर फिल्म 'बॉर्डर' दिखाई गई। लेकिन ये केवल एक फिल्म नहीं थी — यह एक भावनात्मक अनुभव था, जिसने बंदियों को भीतर से झकझोर दिया। तीन घंटे की इस फिल्म में उन्होंने केवल युद्ध नहीं देखा, बल्कि खुद की जिंदगी के उन हिस्सों को देखा, जहाँ शायद वे रास्ता भटक गए थे।

फिल्मों के जरिए आत्ममंथन

फिल्म देखने के बाद बंदियों ने कहा कि उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका जीवन भी देश और समाज के लिए

कीमती हो सकता है। बंदी संदीप गुप्ता ने कहा, "हमने कभी नहीं सोचा था कि जेल में भी हमें ऐसा कुछ देखने और समझने को मिलेगा जो दिल को छू जाए।"

जेल में अब नैतिक शिक्षा की कक्षा

जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य का मानना है कि सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे सजा काटने से बदलाव नहीं आता, उसके लिए जरूरी है सोच और भावना में बदलाव। इसलिए हर शनिवार को अब ऐसी फिल्में दिखाई जाएंगी जो बंदियों को सोचने, समझने और खुद से जुड़ने का अवसर दें। यह पहल सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं — इससे पहले बंदी पेंटिंग, भगवद गीता अध्ययन और संगीत जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा ले चुके हैं।

पुनर्वास की नई परिभाषा

रायपुर सेंट्रल जेल अब उस सोच का प्रतिनिधित्व कर रही है जहां अपराधी नहीं, पुनरावृत्ति से बचाए गए इंसान दिखते हैं। यहां सिर्फ दीवारें नहीं हैं, बल्कि एक नई सोच है — जिसमें हर बंदी को समाज में लौटाने की उम्मीद पल रही है।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में चैंबर ऑफ कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका : विष्णुदेव

रायपुर। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग तेजी से विकास कर रहे हैं, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हम सबको मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ बनाना होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में चैंबर के अध्यक्ष सतीश थीरानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष निकेश बरड़िया सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि



छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 62 वर्षों से कार्यशील है, जिससे 12 लाख व्यापारी जुड़े हैं। प्रदेश के इस सबसे बड़े व्यापारी संगठन के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से निर्वाचन संपन्न हुआ है, जो संगठन की एकजुटता का प्रमाण है। इस परंपरा को यह संगठन आगे भी कायम रखे। प्रदेश में उद्योग और व्यापार की उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

अरुण साव ने दी जानकारी, कहा; सरकार बचे हुए धान की करेगी नीलामी



शहर सत्ता/रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा; सरकार आर्थिक संसाधनों की कमी की पूर्ति करने के लिए तैयार है और सरकार बचे हुए धान की नीलामी करेगी। डिप्टी CM अरुण साव ने कहा, नई औद्योगिक नीति और इनवेस्टर्स मीट का सकारात्मक असर हुआ है। देश के औद्योगिक घरानों का छत्तीसगढ़ के प्रति आकर्षण भी बढ़ा रहा है जो कि सुशासन दर्शाता है। उन्होंने कहा साय सरकार ने किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाई है, कांग्रेस को किसानों की चिंता नहीं थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर निवास में कहा कि, राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदी की है। सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए यह निर्णय लिया है। वहीं उपयोग के बाद जो धान बचे है, उसकी नीलामी की जाएगी।

भड़वाह...

गरीबों से भाईगिरी रईसों से गांधीगिरी

शहरी सरकार में फील गुड नहीं करते परिवार की रोटी के लिए जूझती राधा बाई और पुनाराम देवदास

रईसों के फूड जोन स्टार बक्स, बनाना लीफ और टिनी टॉयज़ की पार्किंग के लिए तोड़ दी गई गुमटी

बिना पार्किंग सिस्टम के वीआईपी इलाके में चल रहे स्टार बक्स, बनाना लीफ, डेली डोज के आउटलेट्स

विशेष संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

शहर सत्ता/रायपुर। क्या हो जब आपके ऊपर छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा, उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी आ जाये और आपके रोजगार पर शहरी सरकार बुलडोजर चला दे ? इस सवाल का कई तरह से जवाब मिलेगा। गरीबी गुजारे में रायपुर शहर के किसी कोने में चाय, नाश्ता या फिर पान की गुमटी चलाकर परिवार का पेट पाल रहा गरीबों का एक बड़ा तबका इन दिनों शहरी सरकार की मुंह देखी कार्रवाई से फील गुड नहीं कर रहा है। जरायम धंधा की बजाए गरीबी गुजारे में मेहनत से रोजी-रोटी कमाने वालों की गुमटियों को रायपुर नगर निगम के अमले ने रौंद दिया है। सड़क किनारे जमीं पर कब्जा करना उनका उद्देश्य नहीं बस दो जून की रोटी कमाना ध्येय है। बावजूद इसके रईसों को बिना पार्किंग सिस्टम के बड़े-बड़े आउटलेट्स चलने देने और आलीशान बंगलों के बहार निगम की सरकारी जमीन घेरकर निजी गार्डन वालों के सामने नतमस्तक निगम अब सिर्फ गरीबों को ही अपना शिकार बना रहा है।

शहर सत्ता किसी भी तरह के कब्जेधारियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों का खेरखाह नहीं है। हम सिर्फ निगम की अमीरों से मां और गरीबों से मौसी का दुलार करने वाली कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं। क्योंकि सबसे वीआईपी मूवमेंट वाले रस्ते सिविल लाइन से पुलिस लाइन हेलीपेड तक और एयरपोर्ट मार्ग में कई आलीशान आउटलेट्स हैं जिनकी वजह से रोज जाम की स्थिति बनती है। इन अमीरजादों को बिना पार्किंग सिस्टम के बिल्डिंग बनाने की अनुमति निगम ने ही दे दी। जबकि सफाई, अवैध निर्माण और यातायात को बाधित करने का आरोप लगाकर बीते सप्ताह गरीबों के ठेले-खोमचों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई निगम अमले ने किया। ऐसा नहीं है कि स्टार बक्स, बनाना लीफ और टिनी टॉयज समेत सिविल लाइन में ही डेली डोज जैसे महंगे रेस्टोरेंट में निगम की सारी शर्तें और नियमों का पालन हो रहा है। दरअसल महापौर, निगम कमिश्नर, जोन कमिश्नर इन पैसे वालों पर कार्रवाई की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। निगम की बाजार व्यवस्था विभाग हो या शहरी योजना शाखा कमोबेश ऐसे ही हालात में है।



निगम की जमीनों पर रईसों का कब्जा

शैलेन्द्र नगर, प्रियदर्शनी नगर, टैगोर नगर, सिविल लाइन, शंकर नगर, आनंद नगर, सुन्दर नगर, विवेकानंद नगर समेत राजधानी रायपुर के संपन्न इलाकों में बड़े-बड़े बंगलों के मालिकों ने क्रोटेन्स, फूल-पीधों के नाम पर शहरी सरकार की अतिरिक्त जमीनें दबा दिया है। इन रईसजादों के घरों के बाहर दर्जनों गाड़ियां यातायात को बाधित करती पार्क की जाती हैं। बड़ी होटलों, रेस्टोरेंट में ड्रेनेज सिस्टम से लेकर पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन निगम, पुलिस और जिला प्रशासन इनकी अनदेखी कर गरीबों की रोजी-रोटी पर ही बुलडोजर चला रहा।



इन अफसरों को भाता है यहां खाना

बनाना लीफ से लेकर हाई टी आयटम्स और महंगी कॉफी पसंद करने वाले निगम, जिला प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे के अधिकारी यहीं से आर्डर करते हैं। सैकरी और नीली-पिली बत्तियों वाली गाड़ियों की आमदरफत यहां दिन-रात रहती है। आउटलेट्स के एक कर्मचारी ने बताया कि कलेक्टर, एसएसपी दफ्तर, निगम कमिश्नर से लेकर संगठन से लेकर कांग्रेस नेताओं को भी हमारा खाना पसंद है। शहर सत्ता ने स्टार बक्स और बनाना लीफ में लगने वाली भीड़ और सड़कों में बेतरतीब कड़ी गाड़ियों की तस्वीरें कैमरे में कैद किया तो उसी वक्त ट्रैफिक पुलिस का एक राजपत्रित अधिकारी परिवार समेत खाकर उतरते दिखे। सुबह से शाम तक की स्थिति शहर सत्ता के कैमरे में कैद है।

बिना पार्किंग-ड्रेनेज का स्टार बक्स

छत्तीसगढ़ कॉलेज के पीछे, तिवारी नर्सिंग होम से लगे स्टार बक्स, बनाना लीफ और टिनी टॉयज़ रेस्टोरेंट संचालित हैं। एक ही बिल्डिंग में संचालित इन फूड जॉन में पार्किंग सिस्टम तो दूर ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। सिविल लाइन से पुलिस लाइन हेलीपेड के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत सभी वीआईपी का काफिला दिन-रात गुजरता है। स्टार बक्स समेत बनाना लीफ में सुबह से देर शाम तक रईसों की जमघट रहती है और उनकी महंगी, लंबी चमचमाती कारें इन्हीं रास्तों को जाम किये रहती है। अस्पताल से लेकर कॉलेज तक और सबसे खतरनाक चौराहे के दोनों तरफ शनिवार, रविवार को सुबह से ही गाड़ियों का काफिला अवैध तरीके से पार्क रहता है। लेकिन इनपर निगम और यातायात पुलिस की अब तक नजरें नहीं पड़ना जांच और अन्वेषण का विषय है। क्योंकि बीजेपी नेता के भतीजे का है यह आउटलेट्स।



यहां एक भी स्टाफ-कर्मि लोकल नहीं है

काश ग्राम पंचायत वाला नियम राजधानी रायपुर समेत शहरों के लिए भी लागू होता तो हमारे प्रदेश का एक निम्न और मध्यमवर्गीय युवा तबका बेरोजगार नहीं रहता। चौंकाने वाली बात यह कि स्टार बक्स, बनाना लीफ, टिनी टॉयज से लेकर डेली डोज तक में निचे से लेकर ऊपर तक बाहरी राज्यों के कर्मचारी नियुक्त हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत समेत शेरों में उद्योगों और कारखानों में लोकल को भी रोजगार देने का पैमाना निर्धारित है। लेकिन, इन आउटलेट्स में छोटे कार्यों के लिए भी यूपी, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली के लोग कार्यरत हैं।

पार्किंग और ड्रेनेज को लेकर हुआ विवाद

राजधानी के बेहतरीन डॉक्टर्स में शुमार डॉक्टर आशीष मल्होत्रा का घर भी स्टार बक्स, बनाना लिफ बिल्डिंग से लगा हुआ है। मसलों की तेज गंध, बेतरतीब वाहनों की पार्किंग से लेकर रेस्टोरेंट बिल्डिंग की नालियों का पानी डॉक्टर मल्होत्रा के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जब असहनीय हुआ तो चिकित्सक और परिवार ने आपत्ति की तो देखते ही देखते आउटलेट्स के संचालकों, बिल्डिंग के मालिक श्री सुराना और स्टाफ के बीच अच्छी खासी तकरार हो गई थी। हालांकि मामला बहुत आगे नहीं बढ़ा और सभी संपन्न, कामयाब लोगों में सुलह हो गई।